● वर्ष-3

● अंक-304

रायपुर, शुक्रवार
02 अगस्त 2024

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› एक बार न्यूजीलैंड भी घूम आए...

कोटे में कोटा पर मुहर, सुको ने पलटा 2004 का अपना फैसला

कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा. इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते: सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोट ने आज एक ऐतिहासिक फ़ैसला दिया. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे में कोटे को मंज़ूरी दे दी है. अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है.सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी यानी उपवर्ग बना सकती है, जिससे मूल और ज़रूरतमंद वर्ग को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा. इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते. इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी. इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को पलट दिया है. मौजूदा पीठ ने 2004 में दिये उस फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है.

डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला-मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि राज्यों को आरक्षण में एससी और एसटी श्रेणी का उप वर्गीकरण करने का अधिकार होगा.उप वर्गीकरण करके एससी और एसटी वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.हालांकि राज्यों को इसके लिए वांछित आंकड़े इकट्ठा करने होंगे ताकि उप वर्गीकरण का औचित्य साबित हो.न्यायमूर्ति बी आर गवई ने अपने फ़ैसले में एससी और एसटी श्रेणी में क्रीमी लेयर बनाने की वकालत भी की ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके.

प्रधान न्यायाधीश ने अपने 140 पृष्ठ के फैसले में कहा, संविधान के अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना) और 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) के तहत सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण देने) के लिए स्वतंत्र है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विजातीय वर्ग हैं. इस प्रकार, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जातियों को आगे वर्गीकृत कर सकता है यदि (ए) भेदभाव के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत है; और (बी) तर्कसंगत सिद्धांत का उप-वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ संबंध है. इस विवादास्पद मुद्दे पर कुल 565 पृष्ठों के छह फैसले लिखे गये. प्रधान न्यायाधीश ने अपनी ओर से और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसले लिखे, जबकि न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने अपने-अपने फैसले लिखे. न्यायमूर्ति त्रिवेदी को छोड़कर अन्य पांच न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत थे.

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने किया विरोध-न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपने 85 पन्नों के असहमति वाले फैसले में कहा कि केवल संसद ही किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकती है या बाहर कर सकती है, तथा राज्यों को इसमें फेरबदल करने का अधिकार नहीं है.उन्होंने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियां एक सजातीय वर्ग हैं, जिन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता.

गांव गरीब और किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

फिर शुरू होगी चरण पादुका और सरस्वती सायकल योजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक श्री किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लम्बे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि खाते में जमा होने के मेसेज के आने की पुष्टि भी की।

दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी।

तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है।

वनाधिकार पत्र का फौती-नामांतरण पाकर हर्षित हुई सुनामनी और बुधरी

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर प्रवास पर गुंडाधुर कृषि कॉलेज कुम्हरावंड में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान वन अधिकार पत्रक धारकों के फौती पर उनके वारिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण वन अधिकार पत्र पुस्तिका का वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों किसान पुस्तिका पाकर जगदलपुर तहसील के कुम्हली निवासी धुरवा महिलाएं सुनामनी एवं बुधरी काफी हर्षित हुईं। उक्त दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने अपने सामाजिक परम्परा के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप को घुरवा समाज के पारंपरिक अंग वस्त्र टेकरा तुवाल (धुरवा गमछा) पहनाकर सम्मानित किया। सुनामनी एवं बुधरी ने नामांतरित वनाधिकार पुस्तिका मिलने पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि अब उन्हें सहकारी समिति से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने सहित खाद-बीज लेने सहूलियत होगी। बैंक से ऋण एवं अन्य कार्यों में इससे मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि बस्तर के धुरवा जनजाति समाज में अपने घर आये मेहमान को टेकरा तुवाल भेंटकर सम्मानित करने की परम्परा है।

नौकरी करने नहीं आया, प्रतिष्ठा तो मठ में मिल जाती-योगी?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काफी आक्रामक अंजाद में दिखे। उन्होंने विपक्ष पर तो निशाना साधा ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने विरोधियों को भी जवाब दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी ने कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा कि ये हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, न ही ये प्रतिष्ठा की भी लड़ाई नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे अपने मठ में मिल जाती। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि राजनीति में उन्हें कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। वैसे तो सीएम योगी अपने सार्वजनिक जीवन के विषय में बहुत सारी बातें कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस बयान के अब अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी सपा समेत समूचे विपक्ष को आईना दिखाते हुए बताया कि राजनीति में जनता की सेवा और सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसमें किन लोगों से उन्हें लड़ना पड़ रहा है इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले और अराजकता फैलाकर आम आदमी जीवन मुहाल करने वाले लोगों से लड़ने के लिए आया हूं। जो ऐसा करेगा वो भुगतेगा भी। सीएम योगी ने कहा ये हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, न ही ये प्रतिष्ठा की भी लड़ाई नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे अपने मठ में मिल जाती।

जम्मू-कश्मीर में तेज हुई विस चुनाव की सुगबुगाहट! चुनाव आयोग के इस आदेश से मिल रहे संकेत

जम्मू। भारत के चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा है। सूत्रों का कहना है कि अगले 10 दिनों में आयोग के केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने की संभावना है। चुनाव निकाय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया से जुड़े उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है जो 30 सितंबर को या उससे पहले तीन साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसी तरह के निर्देश हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्य सचिवों को दिए गए हैं, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। हरियाणा के मामले में, चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर को या उससे पहले तीन साल पूरा करने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कहा है, महाराष्ट्र के लिए यह तारीख 30 नवंबर है और झारखंड के लिए यह 31 दिसंबर है। जम्मू और कश्मीर छह साल से अधिक समय से निर्वाचित सरकार के बिना है और आखिरी विधानसभा चुनाव दिसंबर 2014 में हुए थे।

प्रमुख समाचार

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट

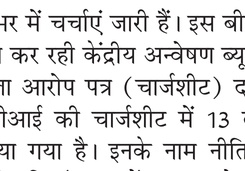

नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर देशभर में चर्चाएं जारी हैं। इस बीच, इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पहला आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर कर दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनके नाम नीतिश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यदुवेंदु , आशुतोष कुमार -1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज का नाम दर्ज है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अब तक कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें बिहार पुलिस द्वारा की गईं 15 गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। सीबीआई का कहना है कि देशभर में 58 जगहों में छापेमारी के बाद 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप पत्र में सीबीआई ने बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

बैडमिंटन के राउंड ऑफ 16 में लक्ष्य की जीत

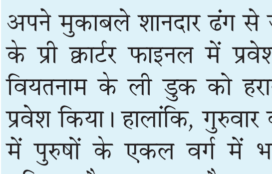

पेरिस। भारतीय बैडमिंटन के स्टार लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय पेरिस ओलंपिक में अपने अपने मुकाबले शानदार ढंग से जीतकर एकल वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रणय ने वियतनाम के ली डुक को हराकर अंतिम-16 में प्रवेश किया। हालांकि, गुरुवार को राउंड ऑफ 16 में पुरुषों के एकल वर्ग में भारत के लिए एक मुश्किल मैच रहा। यह मैच भारत के स्टार शटलर लक्ष्य और प्रणय के बीच हुआ। इस मुकाबले का पहला सेट लक्ष्य ने जीता। उन्होंने 21 मिनट तक चले इस गेम में प्रणय को 21-12 से हराया। वहीं, दूसरे सेट में भी लक्ष्य ने दमदार प्रदर्शन किया और 18 मिनट तक चले गेम में प्रणय को 21-6 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। शुक्रवार को उनका सामना चीनी ताइपे के चू टिन चेन से होगा। पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना एचएस प्रणय से हुआ। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में विश्व रैंकिंग 19 लक्ष्य ने 13वें रैंक के प्रणय को हरा दिया। इसी के साथ प्रणय का सफर पेरिस ओलंपिक में समाप्त हो गया।

'रूस की सेना में काम कर रहे आठ भारतीयों की मौत'

नई दिल्ली। भारत सरकार ने राज्य सभा में एक अहम जानकारी दी है। सदन में सरकार ने बताया कि रूस के सैन्य बलों में काम कर रहे आठ भारतीयों की मौत हो गई है। सरकार ने यह भी बताया कि 12 भारतीयों ने पहले से ही रूसी सैन्य बलों को छोड़ दिया है। राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि रूसी सैन्य बलों में काम कर रहे 63 भारतीय कर्मी जल्दी सेवानिवृत्ति चाहते हैं। कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, 'रूसी सैन्य बलों में काम कर रहे आठ भारतीयों की मौत हुई है।' कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि रूसी सैन्य बलों में काम कर रहे कुछ भारतीयों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जल्द से जल्द कार्यों से मुक्त किया जाए। इन भारतीयों को कथित तौर से अस्पष्ट परिस्थियों में रूस की सेनाओं में शामिल किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि अभी तक वहां मौजूद भारतीयों की सही संख्या की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 12 भारतीय पहले ही रूस की सेना को छोड़ चुके हैं और करीब 63 भारतीय चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जाए।

छत्तीसगढ़ में सेना से होती है रेल की तुलना: संतोष

रायपुर. राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने संसद में आज रेलवे की तारीफ की. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेलवे ने यात्रा तय की है, वह ऐतिहासिक है. हमारे यहां रेल की तुलना सेना से की जाती है. 'अहर्निशं सेवामहे' यद्यपि युद्ध के समय सेना मुस्तैद रहती है, जबकि रेलवे दिन-रात, सर्दी, बारिश, दीवाली, होली, ईद आदि मौकों पर हर समय चलती रहती है. कोरोना काल में हमारी रेल कभी हॉस्पिटल बन जाती है. जिस प्रकार हनुमान जी ने संजीवनी लाने का काम किया, उसी तरह से रेल ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करती है. 'लाइफलाइन ऑफ दि नेशन' हमारा रेलवे है. सांसद पांडेय ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि कोरोना काल से बंद रायपुर से डोंगरगढ़ मेमू ट्रेन को शीघ्र प्रारंभ किया जाए. डोंगरगढ़ से कटघोरा नई रेल लाइन बहुत ही महत्वाकांक्षी है, इसे भी शीघ्र ही शुरू किया जाए. उन्होंने कहा, जब हम ट्रेन में चैन की नींद सो रहे होते हैं तो हजारों रेलकर्मी काम पर लगे होते हैं. जंगल में लेवल क्रॉसिंग गेट हो या मेन स्टेशन हो या वे साइट स्टेशनों पर निष्ठा से कर्तव्य के प्रति, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ हमारे रेलकर्मी मनोयोग और तन्मयता से लगे रहते हैं.

हाईकोर्ट ने स्कूलों के जर्जर भवनों पर लिया संज्ञान

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर संज्ञान लिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन व स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पर स्कूल भवनों को ठीक करने के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने कहा है। हाईकोर्ट ने मामले में कलेक्टर को ही जिम्मेदारी दिए जाने के जवाब पर तीखी टिप्पणी की और कहा कलेक्टर कहां-कहां देखे! शिक्षा सचिव को भी तो कुछ करना चाहिए, सचिव क्या कर रहे हैं? दरअसल, प्रदेश भर के शासकीय स्कूलों में से कई जगहों पर भवन जर्जर हो चुके हैं। बारिश में इन स्कूलो की हालत और भी खराब हो जाती है। इसे लेकर खबरों के सामने आने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बता दें, कि मुख्यमंत्री शाला जतन योजना में 1837 करोड़ सत्र 2022-23 में शासकीय स्कूलों के लिए जारी किया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जब यह जानकारी दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल कहां किया गया, वास्तव में स्कूलों की स्थिति सुधर रही है या सब कागजों पर ही है। इस पर शासन ने कहा कि कलेक्टर अपने डीएमएफ फंड से भी राशि उपलब्ध करा सकते हैं.

संसद समीक्षा

रेल मंत्री ने विपक्ष को खूब सुनाया, कांग्रेस सांसद ने कर दिया बड़ा दावा

केंद्रीय बजट 2024 पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू हुई, विपक्षी दलों ने इसे 卐भेदभावपूर्ण卐 करार दिया, जबकि सरकार ने इसे 卐दूरदर्शी卐 बताया। 22 जुलाई से शुरू हुआ बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। राज्यसभा में ‚क्क सांसद राघव चड्ढा ने भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का आह्वान किया। वहीं, कांग्रेस सांसद द्वारा परिसर में एक हॉल के अंदर बारिश का पानी लीक होने का कथित वीडियो पोस्ट करने के बाद विपक्ष ने नए संसद भवन के स्थायित्व पर सवाल उठाया है। जापान के 'हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स' के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में आए एक संसदीय शिष्टमंडल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही देखी। लोकसभा ने रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को मंजूरी दी। लोकसभा में आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी आक्रामक दिखे।

लोकसभा की कार्यवाही

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन में कहा कि मंत्रियों को सदस्यों के प्रदेशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के पूरक प्रश्न पूछने के बाद यह टिप्पणी की।

- रेलवे की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर 'झूठ की दुकान' चलाने का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि रेलवे में सुरक्षा की 'कवच' प्रणाली के आधुनिक संस्करण को देश के प्रत्येक किलोमीटर रेल नेटवर्क पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर लोकसभा में पिछले दो दिन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए करीब ढाई हजार सामान्य कोच के उत्पादन का विचार सरकार ने किया है, 50 और अमृत ट्रेन के निर्माण का फैसला लिया गया है तथा कम दूरी वाले दो शहरों के बीच वंदे मेट्रो चलाई जाएंगी।

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए हैं जिनका सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को हुआ है। पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए यह आरोप भी लगाया कि अनुसूचित जातियों (एसी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया।

- कार्य स्थलों में महिलाएं के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करने का दावा करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि बीते छह साल में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

राज्यसभा की कार्यवाही

- सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वर्ष 2030 तक शहरों में रहने वालों की संख्या देश की कुल आबादी का 40 प्रतिशत होने का अनुमान है जिसे देखते हुए आधुनिक अवसंरचना निर्माण एवं उनका रखरखाव करना होगा और केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए, इस मंत्रालय के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर कहा गया कि शहरी विकास राज्यों का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया।

- देश में बढ़ते शहरीकरण के बावजूद आवास सहित आधारभूत ढांचे के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के समुचित ढंग से क्रियान्वयन और निगरानी नहीं होने पर चिंता जतायी, वहीं कुछ विपक्षी सदस्यों ने कल हुई वर्षा के कारण नये संसद भवन में जलजमाव को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि बीते दस साल में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए उसके लिए 5.15 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जबकि कभी इस क्षेत्र को देश का अंतिम हिस्सा माना जाता था।

- लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष किए जाने की मांग की गई। वर्तमान में यह 25 वर्ष है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने इस मामले को उठाते हुए हवाला दिया कि भारत एक युवा देश है लेकिन इस अनुपात में युवा राजनीति में नहीं हैं।

- कांग्रेस के प्रमोदी तिवारी ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को रायबरेली में 10 साल पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के बाद भी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित न किए जाने पर चिंता जताई और सरकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह को समाप्त कर इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की मांग की।

बारिश से चारों तरफ भरा पानी, व्यवस्था लाचार

■ **नगर निगम के पूर्व सभापति ने किया खटिया आंदोलन**

कोरबा। कोरबा के हृदय स्थल कोसाबाडी चौक के पास पिछले तीन दिन से सड़क पर पानी भरा है। यहां पानी भरना व्यवसायियों और स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। नगर निगम के पहले सभापति राम नारायण सोनी के नेतृत्व में कुछ लोग पानी में खाट बिछाकर उस पर बैठ गए। विरोध के नए तरीके की जानकारी मिलने पर नगर निगम के अधिकारी सक्रिय हुए और उन्होंने पानी निकासी का प्रयास शुरू कर दिया।

शहर के मध्य कोसाबाडी चौक पर जलभराव की स्थिति पिछले कई सालों से हर बरसात में होती है, जिसके चलते आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों को देखते हुए नगर निगम के पूर्व सभापति राम नारायण सोनी और वार्ड पार्षद निखिल शर्मा कुछ व्यापारियों के साथ आंदोलन पर बैठ गए। सड़क के बीच भरे पानी में खाट और टेबल लेकर बैठ गए, जिसे देख राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई।

पूर्व सभापति राम नारायण सोनी ने बताया कि पिछले कई सालों कोसाबाड़ी चौक पर हर साल बरसात में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। इसकी लिखित शिकायत कई बार नगर निगम और जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मजबूरन आज आंदोलन पर बैठना पड़ा।

पूर्व सभापति ने यह आरोप लगाया कि नगर निगम में बैठे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं, जो शिकायत करने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं देते। जलभराव के कारण चौक में जो दुकाने हैं, वहां ग्राहक नहीं आते। क्योंकि पानी भरा होने के कारण कई ग्राहक वापस चले जाते हैं, ऐसे में उनके व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वार्ड पार्षद निखिल शर्मा ने बताया महापौर मस्त है और जनता त्रस्त है। कई बार उसके वार्ड में जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम में पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम और उनके अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। ऐसे में उन्हें मजबूरन आंदोलन पर बैठना पड़ा।

नगर निगम कोसाबाडी जोन के प्रभारी मनोरंजन सरकार ने बताया कि जलभराव की समस्या को लेकर कई बार यहां नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है, जहां पानी निकासी के लिए आसपास के दुकानदार सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। फिलहाल अभी जेएसईबी मशीन के माध्यम से खुदाई की जा रही है आगे जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा।

इलाज के लिए जा रहे डीवीसीएम कमांडर व ग्रामीण को जवानों ने किया गिरफ्तार

बीजापुर। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि महाराष्ट्र के अहरी एरिया इंचार्ज डीवीसीएम कमांडर व एक ग्रामीण बीमारी की हालत में इलाज कराने जा रहे थे, उन्हें पुलिस जवानों ने हिरासत में ले लिया है।

नक्सलियों के पश्चिम बस्तर और दक्षिण गढ़चिरौली डिवीजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों का आरोप है कि नक्सली नेता महाराष्ट्र के अहरी एरिया इंचार्ज डीवीसीएम कमांडर विकास उर्फ जट्टी चैनु बीमारी की हालत में इलाज कराने फरसेगढ़ के रास्ते से जा रहे थे, तभी सोमनपल्ली के पास पुलिस जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट में कहा है कि नक्सली नेता के साथ एक ग्रामीण विज्जु वेंडजा को भी गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों का आरोप है कि दोनों को यातनायें दी जा रही है।

नक्सली नेताओं ने गिरफ्तार नक्सली नेता को कोर्ट में पेश कर मुफ्त इलाज करने और ग्रामीण विज्जु वेंडजा को निशर्त रिहा करने की मांग की है। नक्सलियों का कहना है कि गिरफ्तार नक्सली नेता विकास को अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी।

जगदलपुर में शहीदी सप्ताह मना रहे नक्सली, कई ट्रेनों को रोका गया

जगदलपुर। नक्सली अपने नक्सली भाइयों की मौत को लेकर हर वर्ष 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस बार भी नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, जिसके चलते फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। रेल प्रशासन ने परिचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की है। वहीं, पैसेंजर ट्रेन को रोक भी दिया गया है।

वाणिज्यिक प्रबंधक के संदीप ने बताया कि केके रेल लाइन पर नक्सलियों का खौफ हमेशा से देखा जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक से आठ अगस्त तक आवागमन प्रभावित रहेगा। विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर ट्रेन भी दंतेवाड़ा में रोकी जाएगी। दंतेवाड़ा से किरंदुल के बीच ट्रेन सुविधा नहीं मिलेगी। नाईट एक्सप्रेस का परिचालन भी दंतेवाड़ा तक ही किया जाएगा। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते ईको रेलवे ने यह निर्णय लिया है।

9 कोचिंग संस्थानों में छापेमारी, 7 को नोटिस

बिलासपुर। दिल्ली के राऊ कोचिंग सेंटर में बारिश के दौरान तीन प्रतियोगी छात्रों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाना शुरु कर दिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों में किसी भी प्रकार की घटना की प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के तहत बिलासपुर एसडीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने शहर के एक लाइब्रेरी समेत 9 सेंटर्स की जांच की। जांच में कहीं भी मापदंडों के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाई गई। प्रशासन ने 7 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन दिनों के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।

जांच टीम में एसडीएम पीयूष तिवारी, प्रशिक्षु आईएएस सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप, नगर निगम अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, नगर सेना कमांडेट दीपांकर नाथ और अपर संचालक डॉ. प्रवीण पांडेय शामिल थे। अधिकारियों ने मंगला क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थानों की जांच की। दिल्ली आईएएस इंस्टीट्यूट में जांच के दौरान व्यवस्था कुछ ठीक पाई गई और फायर सेफ्टी की भी व्यवस्था थी। इसके बाद कल्पवृक्ष और भारतीय कृषि कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट की जांच की गई, जहां कई खामियां मिलीं। टीम ने राजेंद्र नगर और दयालबंद क्षेत्र में स्थित पटेल ट्यूटोरियल्स, सहस्त्रतार्थ कोचिंग सेंटर, हरिण राजपूत ट्यूटोरियल्स और सिद्धी लाइब्रेरी की भी जांच की। सभी जगहों पर मापदंडों के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाई गई, जिस पर तुरंत ही सात कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर दिया गया। इन कोचिंग सेंटरों को तीन दिनों के भीतर मापदंडों के अनुरूप व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस सरकार में शुरू हुई योजना को भाजपा ने किया बंद

राजीव युवा मितान क्लब : जारी की गई राशि हो रहा ऑडिट

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा राजीव युवा मितान क्लब की शुरूआत की गई थी। सरकार बदलते ही यह योजना भी वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा न केवल बंद की गई, बल्कि इसके तहत जारी किए गए करोड़ों रुपये की राशि का अब ऑडिट भी कराया जा रहा है। इसे लेकर महासमुंद में भाजपा-कांग्रेस में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार की योजना बता रही है तो वहीं कांग्रेस जैसी पार्टी वैसी उसकी सोच का बयान देती नजर आ रही है।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाए जा रहे राजीव युवा मितान क्लब योजना के बंद होने के बाद अब बनाए गए क्लबों के द्वारा किये गए खर्च राशि का ऑडिट कराया जा रहा है। इसके साथ ही क्लबों के खातों को सीज कर शेष राशि की वसूली भी की जा रही है। जो क्लब खर्च किए गए राशि के बिल पेश नहीं कर रहे और ऑडिट नहीं करा रहे हैं उन्हें नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

महासमुंद में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा कुल 582 क्लब बनाये गए थे। सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल एवं अन्य गतिविधियों के लिए इन क्लबों को एक साल में 5 करोड़ 82 लाख की राशि का वितरण किया गया था। वर्ष 2022-23 और 23 24 में इन क्लबों में राशि वितरण किया गया, लेकिन पूर्व सरकार में दो सालों तक खर्च की गई राशि का कोई ऑडिट या हिसाब नहीं लिया गया था।

छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलते ही अब न केवल इस योजना को बंद किया गया है, बल्कि खर्च की गई राशि की ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। जिले के बसना ब्लॉक में करीब 6 लाख की राशि वापस ली गई है तो वही महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा और सरायपाली ब्लॉक से 20 लाख से अधिक की राशि की वापसी होनी अभी बाकी है। जिसकी प्रक्रिया लगातार की जा रही है। महासमुंद शहर में नगर पालिका सीएमओ ने नगरी निकाय के सभी क्लबों को राशि वापसी करने और खाते का ऑडिट करने के लिए नोटिस भी जारी किया है।

पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने जहां इस योजना को खाओ पियो योजना बताते हुए भ्रष्टाचार का एक पहलू होने का आरोप लगाया है। डॉ. विमल चोपड़ा का कहना है कि केवल 10त्न की राशि अन्य गतिविधियों में खर्च की गई थी। जबकि 90त्न की राशि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने, कार्यकर्ताओं में दारू पार्टी करने के लिए खर्च की है। उन्होंने इस योजना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना का निर्माण और संचालन भी कांग्रेस के विधायकों के इशारों पर होता था।

वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने भाजपा के इस आरोप को अनर्गल बयानबाजी बताते हुए कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसा बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब योजना की शुरुआत की गई थी तो कांग्रेस सरकार की हम मनसा थी कि सामाजिक उत्थान हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का उत्थान हो, छत्तीसगढ़िया खेलकूद को बढ़ावा मिले, युवाओं को आगे लाने की सोच भूपेश बघेल की थी, जो भाजपा को अब पच नहीं रहा है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय चलाए जा रहे राजीव युवा मितान क्लबों के सभी खाते सीज कर दिए हैं। क्लबों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के लिए एक साल में 132 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किये गए थे। जिनके द्वारा अब खर्च किए गए राशि का ऑडिट की जा रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या वाकई इस योजना में भ्रष्टाचार निकलकर सामने आएगा, या फिर यह बातें केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी।

जशपुर में दल से बिछड़े दंतैल हाथी का तांडव

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का है। यहां बीते रात एक जंगली दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अपने परिवार को बचाने के लिए परिवार वालों को दूसरी ओर भेज रहा था। इस दौरान जंगली दंतैल हाथी की चपेट में वो आ गया। फिलहाल वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची है। शव का पंचनामा कर पीड़ित परिवार को सहायता राशी दी गई है। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

दरअसल, घटना जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार रात हाथी के हमले से क्षतिग्रस्त हुए मकान से परिजनों को बचाने के लिए एक शख्स दूसरे जगह परिवारवालों को शिफ्ट कर रहा था। इस दौरान हाथी ने शख्स पर हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक जगरनाथ राम की उम्र 55 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हाथियों के दल से अलग हुआ एक दंतैल हाथी बुधवार रात लगभग 3 से 4 गांवों में 10 से 12 घरों को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने कहा तपकरा वन परिक्षेत्र से एक दंतैल हाथी नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर ग्राम के डूमर डांड़ में बीती रात 55 वर्षीय ग्रामीण को हाथी ने कुचलकर मार डाला है। क्षेत्र में अलग-अलग 5 से 6 दंतैल हाथी घूम रहे हैं। वन विभाग और वन मित्र की ओर से ग्रामीणों को सचेत भी किया जा रहा है। मृतक के परिजनों को तत्कालीन सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जंगल में रहने वाले लोगों को बाहरी क्षेत्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि बुधवार रात को दंतैल हाथी के तांडव से कई लोगों को नुकसान पहुंचा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विलासराव ने सम्हाला मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का पदभार

बिलासपुर। डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने 31 जुलाई को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यह जिम्मेदारी समीर कान्त माथुर से ली, जो वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उप महाप्रबंधक (सामान्य) के पद पर कार्यरत हैं और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव भारतीय रेलवे परिचालन सेवा (आईआरटीएस) के 2014 बैच के अधिकारी हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पहले, वे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मुख्यालय, बिलासपुर में उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवा) के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा, उन्होंने मध्य रेलवे के सोलापुर, भुसावल और नागपुर रेल मंडल में परिचालन और वाणिज्य विभाग के विभिन्न पदों पर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में मंडल वाणिज्य प्रबंधक तथा उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (गति शक्ति) के पदों पर भी सेवाएं दी हैं।

स्कूली छात्रों से भरी टाटा मैजिक खेत में पलटी

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सेमलिया गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टला। स्कूली विद्यार्थियों से भरी एक टाटा मैजिक वाहन रास्ते से अचानक पलटकर खेत में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी छात्र को चोंट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार, जिले कि कुटेला क्षेत्र स्थित सेंट विसेंट पलोटी स्कूल के दस-बारह छात्र-छात्राएं टाटा मैजिक में सवार थे। वाहन सभी विद्यार्थियों को स्कूल लेकर जा रही थी। इसी दौरान सरायपाली के सेमलिया गांव में वाहन अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतर कर खेत में जा पलटी। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से मुलाकात कर यह सुनिश्चित किया कि सभी स्टूडेंट्स सही सलामत हैं या नहीं। इस घटना में विद्यार्थियों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यह राहत की बात रही कि किसी भी विद्यार्थी को चोंट नहीं पहुंची है और सभी सुरक्षित रूप से वाहन से बाहर निकले।

कबीरधाम में बारिश का दौर जारी

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में गुरुवार को 24.9 मिमी तक बारिश हो हुई। इस मानसून एक जून से एक अगस्त के बीच अब तक 472.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वर्तमान में हो रही बारिश का प्रभाव स्कूलों में दिखाई दे रहा है। जिले के ग्रामीण अंचल में विभिन्न स्कूल में बारिश का पानी भर गया है। पंडरिया ब्लॉक के ग्राम नरौली के पूर्व व प्राथमिक स्कूल में घुटनों तक पानी भर गया है, ऐसे में यहां गुरुवार को पढ़ाई नहीं हो सकी। इस स्कूल में 200 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहां के स्कूल तक आने-जाने के लिए सड़क का आभाव है। गली में कीचड़ भर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पानी की निकासी नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है। वर्तमान में स्कूल परिसर से पानी निकासी की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्र में बारिश का असर दिखाई दिया है। दूसरी ओर जिले में शासकीय स्कूलों का विशेष प्राथमिकता के साथ मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। इसके लिए 42 करोड़ 19 लाख 88 हजार रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उफनाती हुई नदी में बहकर 20 किलोमीटर दूर पहुंची महिला

रायगढ़। ओडिसा के झारसुगडा थाना क्षेत्र के पुसल्दा गांव के मछुआरों ने उफनती महानदी में बहती हुई एक महिला को सुरक्षित बचाया है। मछुआरों के द्वारा महिला से प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम सरोजनी रणवीर बताते हुए कहा कि वह नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोर्रा गांव की रहने वाली है और तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बहकर यहां तक पहुंची है। उफनती हुई महानदी में 20 किलोमीटर तक बहकर आई महिला के दोनों पैरों में लोहे की जंजीर से बंधे होने के बावजूद महिला की जान बच गई। इसके बाद से उसे बचाने वाले मछुआरों भी इसे आश्चर्य मान रहे हैं। महिला पूरी तरह से स्वस्थ है और महिला को उसके गांव भेजने की तैयारी की जा रही है। महानदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने बताया कि उन लोगों ने महिला को देखे तो वह बहकर आ रही थी बाकी जो लोग थे उन लोगों ने देखा। जैसे पास में किनारे दिखी तो सभी दौड़कर गये, उसे बचाकर लाये और नाव में लाकर बैठाया।

एसीसी सीमेंट फैक्टरी में करंट लगने से मजदूर की गई जान

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एसीसी सीमेंट फैक्टरी में काम के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मजदूर हाई वोल्टेज करंट से पूरी तरह झुलस गया था। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों ने स्पर्श हॉस्पिटल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मो. आबिद (28) निवासी जामुल नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर-2 विश्वकर्मा चौक के रूप में हुई है। वह एसीसी सीमेंट प्लांट में पिछले 10-12 साल से इलेक्ट्रीशियन के पद पर काम कर रहा था। वह अपने दो बच्चे और पत्नी के साथ रहता था। रोजाना की तरह आबिद काम पर फैक्टरी गया था। गोडाउन में करंट सप्लाई की खराबी को सुधार कर रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया और उसका शरीर काला पड़ गया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जामुल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा।

जूता, कपड़ा और रिश्ता जब कष्ट दें उसे त्याग दो : प्रदीप मिश्रा

■ **भिलाई में शिव महापुराण के आखिरी दिन कथावाचक का संदेश**

भिलाई। जयंती स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा को सुनने लाखों लोग पहुंचे। एक हफ्ते तक चले कथा में लोगों ने शिव महापुराण और पंडित प्रदीप मिश्रा को सुना। कथा में महिलाओं की ज्यादा भीड़ नजर आई। कथा के आखिरी दिन पूरा जयंती स्टेडियम श्रद्धालुओं से भरा रहा। कथा के आखिरी में कथावाचक ने लोगों से शिव आराधना और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आह्वान किया। महापुराण के दौरान उन्होंने भक्तों को कई ज्ञान की बातें भी बताई।

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा अगर आप ऑफिस जाते हैं और पहली फाइल उठाने से ही टेंशन आ जाता है तो आपका नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। इसी तरह घर में अगर कलेश हो रहा है, परिवार वालों से विवाद हो रहा है तो घर आने का मन नहीं करता इसलिए नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करें और घर ऐसा हो जहां आने का मन करें।

अगर आपको कोई कपड़ा या जूता टाइट होने की वजह से कष्ट देता है तो आप उसे नहीं पहनते और छोड़ देते हैं। इसी तरह जो रिश्ता जिंदगी में कष्ट दें उसको आप त्याग दो। जिंदगी भर आप मेहनत करो और धन दौलत कमा कर घर बंगला बना लो पर अगर घर में बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, चिल्लाकर बात करते हैं तो उस धन दौलत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना और शंकर का घर।

पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर ले जाती है तो बच्चे को कुछ नहीं होता लेकिन बिल्ली जब चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है तो वो बचता नहीं हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनोगे तो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर निकल जाओगे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।

हनुमान जी के मंदिर में राम-सीता का होना जरूरी नहीं है, परंतु राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरुरी हैं। क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम की सच्चे मन से भक्ति की है और जहां राम का नाम आता है वहां हनुमान जी का जिक्र जरूर होता है।

पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्यार और प्रेम में अंतर समझते हुए कहा कि प्यार संसार से होता है और प्रेम परमात्मा से होता है। प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते है। और प्रेम से प्रभु मिलते है। उन्होंने कहा कि, संसार के लोगों से प्यार होगा तो मोबाइल में बैलेंस डल जाएगा पर प्रेम किया तो उम्र का बैलेंस डल जाता हैं। इसलिए प्रेम ईश्वर से करो कभी धोखा नहीं मिलेगा।

अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो, अपना कंट्रोल किसी और को मत दो। जिंदगी के तीन क्रम है, सबसे पहले लोग आपके काम पर हसेंगे, फिर आप जब आगे बढ़ने लगेंगे तब दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे। जब आप बहुत उन्नति की सीढ़ी में चढ़ जाओगे तो लोग आपका हाथ जोड़ कर सम्मान करेंगे। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहो।

सेंट्रल जेल में चला धारदार हथियार

सरगुजा। सेंट्रल जेल के अंदर बंदी पर धारदार हथियार से कैदी पर हमला करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने अब अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी बंदी के खिलाफ मुख्य प्रहरी की शिकायत पर कार्रवाई की है। लेकिन इस घटना के बाद अब भी बड़ा सवाल यही है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी के पास बैरक में धारदार हथियार ब्लेड कैसे पहुंचा।

धमतरी के श्रद्धा नगर आमा तालाब रोड निवासी उत्तम रामटेके पिता देवन्द्र रामटेके को न्यायालय से धारा 302, 27(1) आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के बाद कैदी को रायपुर जेल से प्रशासनिक आधार पर सेंट्रल जेल सरगुजा भेजा गया था। बंदी उत्तम रामटेके जेल के अंदर बैरक नंबर 8 में रखा गया था।

28 जुलाई की शाम लगभग साढ़े पांच बजे बैरक में लूडो खेलने के दौरान हुए विवाद में उत्तम रामटेके ने धारा 306 के तहत सजायाफ्ता कैदी विनय पांडेय आत्मज चन्द्रसेन पांडेय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। ब्लेड के हमले में विनय कुमार पांडेय को चेहरे पर चोट आई थी। इस दौरान बैरक में मौजूद बंदी सूरज कुजूर ने बीच बचाव किया।

इस मामले में सेंट्रल जेल के मुख्य प्रहरी तारा प्रकाश बाग ने मणिपुर थाने में घटना की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी और बंदी उत्तम रामटेके के खिलाफ बीएनएस की धारा 118(1) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

संक्षिप्त समाचार

एक दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय का आत्मीय स्वागत

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक

दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। सीएम साय के साथ में वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे भी पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर विधायक किरणदेव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, महापौर सफीरा साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, लच्छुराम कश्यप, सुभाऊ कश्यप के साथ-साथ बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, सीसीएफ आरसी दुग्गा, कलेक्टर विजय दयाराम के, एसपी शलभ सिन्हा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

पं. रविशंकर शुक्ल व विद्याचरण शुक्ल की जयंती आज

रायपुर। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं

अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल एवं झीरम घाटी के शहीद व पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल की जयंती 2 अगस्त को प्रात: 10 बजे श्री विद्याचरण शुक्ल उद्यान नगर पालिक निगम मुख्यालय के सामने व 10.30 बजे छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद के केन्द्रीय कार्यालय शुक्ल भवन में पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई जायेगी।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहायता केंद्र आज से फिर होगा शुरु

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राजधानी में

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय सहायता केंद्र आगामी 2 अगस्त से फिर शुरू होने जा रहा है। आम नागरिकों की समस्याओं के निदान और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किए गए इस केंद्र में प्रतिदिन बारी-बारी प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। विधानसभा सत्र की व्यस्तता के चलते कुछ दिनों तक यह केंद्र स्थगित था जो 2 अगस्त से फिर शुरू हो रहा है। आगामी 2 अगस्त को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यकर्ताओं एवं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा ने सहायता केंद्र की शुरुआत की है और सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों के समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने बस्तर जिला अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोईघर का किया लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर प्रवास के दौरान जिला अस्पताल (महारानी अस्पताल) परिसर में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित अन्नपूर्णा रसोईघर का लोकार्पण किया। अन्नपूर्णा रसोईघर डीएमएफटी मद के तहत 01 करोड़ 72 लाख 76 हजार की लागत से स्थापित मॉड्यूलर किचन एवं सामग्री युक्त रसोईघर है। इस रसोईघर का संचालन मां दन्तेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा।

भाजपा नेता और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा नेता और अस्पताल स्टाफ के बीज जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेपी सर्जिकल हॉस्पिटल की है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, भाजपा मंडल महामंत्री मनीष मिश्रा और अस्पताल स्टाफ के बीच बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में तब्दील हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन जहां भाजपा नेता पर मारपीट का आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि एक मरीज के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही।

जीएसटी में सुधार के लिए जीओएम का पुनर्गठन, ओपी चौधरी बनाए गए सदस्य

रायपुर। जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं। नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जल शक्ति अभियान के जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

■ साय ने परिसर स्थित वीर शहीद गुण्डाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जल संरक्षण के प्रति बस्तर जिलावासियों को जागरुक करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर जगदलपुर से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गाँवों में पहुँचकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक करेगा। बस्तर जिले में जल संसाधन विभाग की 108 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसमे विभिन्न वृहद टैंक, स्टॉप डैम, एनिकट, मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है।

जिले में 95 अमृत सरोवर बनाये जा रहे हैं जिसमें से 75 पूर्ण हो चुके हैं। इनके निर्माण में महिलाओं की सहभागिता प्राथमिकता में रही है। नारी शक्ति को शामिल करते हुए,जिले में मनरेगा अंतर्गत 3 हज़ार 881 जिओ-टैग्ड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये गए हैं, जिसमे से लोहण्डीगुडा ब्लाक में 695, दरभा में 1863, बास्तानार में 391, जगदलपुर में 402 बकावंड में 530, तोकापाल में 306 एवं बस्तर में 425 जल संरक्षण संरचनात्यें शामिल है । साथ ही जल संरक्षण कार्ययोजना रिपोर्ट के आधार पर कुल 1305 नवीन स्ट्रक्चर प्रस्तावित हैं। जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 32 एकड़ क्षेत्रफल में सघन वृक्षारोपण किया गया हैं। जिले में ब्लाक प्लांटेशन तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण में कुल 1287781 वृक्ष लगाए

गए हैं।

जल जीवन मिशन अंतर्गत 2385 महिलाओं को पानी के परिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिसका लाभ जिले के सुदूर क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। चूंकि नारी का स्थान हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है जो अपने आवास के साथ-साथ पर्यावरण की भी संरक्षिका रही है। अत: नारी शक्ति से जल शक्ति सार्थक सिद्ध होता है। इसी तरह बस्तर जिले के कुल 433 ग्राम पंचायतों के 614 ग्रामों में 11979 हैण्ड पंप लगाए गए हैं जो पीने के पानी हेतु जीवन दायी सिद्ध हो रहा है साथ ही साथ 140 ग्राम पंचायत में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। जिले में स्पॉट सोर्स अंतर्गत 130 ग्राम पंचायतों में 61 में सोलर तथा 69 में पॉवर पंप द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है।

बस्तर जिले विभिन्न एजेंसियों को शामिल करते हुए कुल 718 सोलर पॉवर पंप स्थापित किए गए हैं। जिले में जल जीवन मिशन किसी अमृत प्रदाय योजना से कम नहीं, इस योजनान्तर्गत जिले के कुल 614 ग्रामों में 630 योजना, 153049 एफएचटीसी, 543 ओएचटी, 992 सोलर पंप तथा 393 सोलर जल प्रदाय निर्मित हैं, घर में पेयजल की महत्ता परिवार की नारी से अधिक शायद किसी को भी न हो चूंकि वही है जो पानी के कमी पर बूंद-बूंद का संरक्षण स्वयं करती है अत: पेयजल हेतु भी नारी शक्ति से जल शक्ति उचित जान पड़ता है। गौरतलब है कि जल शक्ति अभियान : कैच द रेन 2022 अभियान की शुरुआत देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 मार्च 2022 को वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण,पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों/बावडियों बावलियों का नवीनीकरण,संरचनाओं का पुन: उपयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास,आईभूमियों का पुनरुद्धार और बाद-तटों की सुरक्षा, जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण स्प्रिंग-शेड विकास, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना,वैज्ञानिक-जिला जल संरक्षण योजना का विकास, नदी नाली का पुनर्जीवन, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र की स्थापना इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था।

मुख्यमंत्री ने आम का पौधा रोपकर एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर ज़िले में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को आम के पौधों का वितरण भी किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण, वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 95 लाख 85 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने किया तीन एसडीएम कार्यालय और दो थाना कार्यालय का लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बस्तर जिले के प्रवास के दौरान दन्तेश्वरी कन्या कॉलेज के सामने नवीन राजस्व कार्यालय परिसर में 48 - 48.लाख की लागत से निर्मित तीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा तथा 250-250 लाख की लागत से निर्मित लोहण्डीगुड़ा और बुरगुम थाना का लोकार्पण किया।

नवीन अनुविभागीय कार्यालय के खुलने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जगदलपुर के लगभग तीन लाख, तोकापाल के लगभग दो लाख 65 हजार और लोहण्डीगुड़ा के लगभग एक लाख आबादी को सुविधा मिलेगी। इससे पहले जगदलपुर का एसडीएम कार्यालय संयुक्त कार्यालय में संचालित किया जाता था, इसी प्रकार तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा का अनुविभागीय कार्यालय तहसील कार्यालय परिसर में संचालित होता था। नवीन थाना भवनों के निर्माण से क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व कार्यालय परिसर में 66.49 लाख की लागत से नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। इस तहसील कार्यालय में जगदलपुर और नजूल न्यायालय के साथ-साथ फ्रेजरपुर, कुरुंदी, मार्केल का

न्यायालय नायब तहसीलदार भी बनाया गया है। पूर्व में यह तहसील कार्यालय अपने पुराने भवन में संचालित की जा रही थी, न्यायालयों का विस्तार होने से पुराने भवन में जगह की दिक्कत और जनता की सहूलियत की दृष्टिकोण से नए जगह पर स्थानांतरित किया गया है। पुराने तहसील भवन को बस्तर दशहरा में शामिल होने वाले देवी-देवताओं और उनके सेवादारों के ठहरने के लिए हेरिटेज ग्राउंड के रूप में विकसित किया जा रहा है।

लोकार्पण के अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप,जगदलपुर विधायक श्री किरणदेव, विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, महापौर सफीरा साहू, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी., कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

अब श्रमिकों को नहीं करना होगा इंतजार, एक क्लिक में जारी होगी योजनाओं की राशि

श्रम मंत्री लखनलाल ने अफसरों को दिए निर्देश

रायपुर। श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अब राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है। इससे हितग्राहियों को बारङ्कबार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर श्रम मंत्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाएं, जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके। बैठक में अलरमेल मंगई डी सचिव श्रम विभाग, सविता मिश्रा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल समेत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कोचिंग मिलेगी। वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित किया जाएगा।

बोर्ड की बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही है, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई।

महाविद्यालय के छात्रों व अध्यापकों ने किया वृक्षारोपण

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने के आव्हान पर आज विकास शिक्षा महाविद्यालय डूमरतराई के छात्रों व अध्यापकों ने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के महत्व व आवश्यकता को देखते हुए विकास शिक्षा महाविद्यालय के छात्रों व अध्यापकों ने महाविद्यालय परिसर में अजय तिवारी अध्यक्ष महन्त लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय एवं डॉ. सुरेश शुक्ला अध्यक्ष विकास शिक्षण संस्थान के आतिथ्य में महाविद्यालय परिसर में आम व जामुन के पौधे अपनी-अपनी माता जी के नाम लगाए। इस अवसर पर महाविद्यालय के अध्यापकगण श्रीमती अनुकृति शुक्ला हिमलता साहू, वर्षा अग्रवाल, डेनिता साहू खुशबू बाला, डोलेश्वरी होता, उमेश साहू बृजेश संगीता दुबे वंदना यदु कुमार एवं छात्राध्यापकगण आरजू तिर्की, जागृति साहू, निशा, प्रीति डहरिया, पूनम, सीतेश्वरी, वीणा चेतना विजयलक्ष्मी आदि उपस्थित थे।

व्यायाम शाला युवाओं को ओलंपिक के लिए कर रहा तैयार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और उन्हें ओलंपिक तक का सफर तय करने के लिए बुधराम सारंग की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। रायपुर के गुढ़ियारी में सतनामीपारा में सारंग भाईयों की छोटी सी व्यायाम शाला में लगभग 50 खिलाड़ियों को वेट लिफ्टिंग की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर रुस्तम सारंग ने बताया कि व्यायाम शाला में सुबह 5 बजे से 3 अलग-अलग शिफ्टों में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन खिलाड़ियों में लड़कियां भी शामिल हैं। रुस्तम सारंग ने बताया कि फिलहाल उनका फोकस खिलाड़ियों को आने वाली सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीताने का है।

मीडिया से बातचीत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और सीनियर कोच अजय दीप सारंग ने बताया कि इन दिनों पेरिस ओलंपिक गेम चल रहा है। उन्होंने भी 2012 से तीन बार अलग-अलग सत्रों में ओलंपिक में जाने प्रयास किया। लेकिन जागरुकता की कमी के चलते ओलंपिक में नहीं पहुंच पाए। छत्तीसगढ़ के एक भी बच्चे 2016 के बाद ओलंपिक में नहीं पहुंचे। इसलिए वे बच्चों को नशे की लत से दूर रखने और और यहां से बच्चे नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, और ओलंपिक में पहुंचाने के लिए लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं।

अजय दीप सारंग ने कहा कि सबसे पहले मेरे पिताजी बुधराम ने सारंग मोहल्ले के आसपास के बच्चे और युवा नशे और गलत संगतियों में ना आकर्षित न हो जाएं, इस उद्देश्य से वेट लिफ्टिंग सेंटर की शुरूआत की थी। बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस व्यायाम शाला को 2002 में खोला गया था।

नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के सम्मेलन पर डिप्टी सीएम साव का तंज

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के सम्मेलन पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा सभी राजनीतिक दलों को चुनाव की तैयारी करने का अधिकार है। कांग्रेस का जो हश्र विधानसभा और लोकसभा में हुआ है, वही हश्र आने वाले चुनाव में भी होगा। कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, वह अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं।

कांग्रेस द्वारा लखेश्वर बघेल को उपनेता प्रतिपक्ष बनाने की कवायद पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि किसको क्या बनाएंगे कांग्रेस का मामला है। जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म हो गई है। कांग्रेस जनहित, प्रदेश हित और देश हित से दूर जा चुकी है।

वहीं यूपीएससी के तर्ज पर सीजीपीएससी द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन फार्म भरे जाने पर अरुण साव ने कहा कि एक समिति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो उसके लिए यह कमेटी बनाई गई है। कमेटी का रिपोर्ट आनी बाकी है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी पारदर्शिता निष्पक्षता लेकर आना है। हमारी सरकार उस पर विचार कर रही है।

भरत साहू ने देश की खातिर दिया सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद भरत साहू के रायपुर में लक्ष्मी नगर, मोवा स्थित घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने शहीद के पिता श्री रामा साहू, बड़े भाई श्री मनसा राम साहू, उनकी बेटियों और अन्य परिजनों से मुलाकात की। रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू और साहू समाज के अनेक पदाधिकारी भी इस दौरान उनके साथ थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने परिजनों से कहा कि श्री भरत साहू ने देश की खातिर अपना बलिदान दिया है। आपको उन पर गर्व करना चाहिए। सरकार तत्परता से परिवार की पूरी मदद करेगी। उन्होंने तत्काल ही रायपुर नगर निगम के आयुक्त से बातकर राज्य कैबिनेट के निर्णय अनुसार जल्दी ही मोवा चौक पर शहीद भरत साहू की मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए।

श्री साव शहीद जवान की दोनों बेटियों से भी मिले और बात की। उनकी छह साल की बड़ी बेटी पिता की तरह देश सेवा करने भारतीय पुलिस सेवा में जाना चाहती है। वहीं पहली कक्षा में पढने वाली छोटी बेटी ने आर्मी ज्वाइन करने की बात कही। श्री साव ने उनकी बातें सुनकर कहा कि पढ़-लिखकर अपने पिता के सपने को साकार करना है। अपने पिता की तरह देश का मान बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री से शहीद भरत साहू के पिता श्री रामा साहू ने कहा कि मेरा बेटा शुरू से बस्तर में तैनात था। उनकी याद हमेशा आएगी, वह अमर हो गया। पूरे परिवार को उन पर गर्व है।

**OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, E/M CIRCLE, RAIPUR (C.G.)**

e-Procurement Tender Notice

Online tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh from contractors, **C.G. P.W.D in new Registration system (unified Registration system)** for the following work :-

NIT No.	Name of work	Probable amount of contract
03A/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No156780 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	For Providing Electrification Work (Zonal) For at New Circuit House & Minister Bunglow Section Civil line Raipur Under P.W.D. E&M SubDn. Vidhansabha, Raipur CG	Rs 90.00 Lacs
04/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No 156772 Registered contractor class in "C" & above For Form "A" (Item Rate Tender)	NIT SCHEDULE FOR PROVIDING, INSTALLATION AND ORDINARY MAINTENANCE OF LV PACKAGES ELECTRONIC ITEMS TO PROPOSED WORK IN GOVT. RESIDENTIAL & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS UNDER PWD E/M DIVISION RAIPUR (C.G)	Rs 87.00 Lacs
05/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No156773 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	NIT SCHEDULE FOR PROVIDING ELECTRIFICATION WORK TO PROPOSED DEPOSIT, MOW & SR WORK IN GOVT. RESIDENTIAL & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS UNDER PWD E/M DIVISION RAIPUR (CG)	Rs 93.00 Lacs
07/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No156779 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	PROVIDING MAINTENANCE WORK OF ALL TYPES OF AIR CONDITIONER INSTALLED UNDER PWD E/M DIVISION RAIPUR (C.G.) Make:- Voltas/ Bluestar/Panasonic/Carrier/ O General/Daikin/ Mitsubishi/Haier/Hitachi	Rs 48.00 Lacs
08/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No156809 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	FOR PROVIDING AND FIXING OW/ MOW/ SR/OR/ ADDITION AND ALTERATION/ DEPOSIT AND OTHER ELECTRIFICATION WORK IN DHARSIWA, ABHANPUR, TILDA, KHARORA, AND MLA REST HOUSE SECTION UNDER PWD E&M DIVISION RAIPUR (UNDER PWD E/M SUB-DIVISION VIDHANSABHA, RAIPUR	Rs 91.11 Lacs
09/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No156812 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	P/F EXPECTED 33/11 KV, LT LINE, TRANSFORMER DP SHIFTING AND HEIGHT RISING WORK AND OTHER ELECTRIFICATION WORK UNDER E/M VIDHANSABHA SUBDIVISION, RAIPUR	Rs 98.27 Lacs
10/SE E/M/2024-2025 (I Call) System Tender No 156807 Registered contractor class in "C" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	NIT SCHEDULE FOR FIRE ALARM WORK IN PT. JNM MEDICAL COLLEGE, HOSTEL BUILDINGS & OLD AUDITORIUM BUILDING AT PT JN.M. MEDICAL COLLEGE PARISAR, CENTRAL JAIL ROAD RAIPUR (C.G.)	Rs 199.53 Lacs
11/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No156816 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	P/F EXPECTED 33/11 KV, LT LINE, TRANSFORMER DP SHIFTING AND HEIGHT RISING WORK AND OTHER ELECTRIFICATION WORK UNDER E/M DIVISION, RAIPUR	Rs 93.28 Lacs
106/SE E/M/2024-2025 (1Call) System Tender No 156765 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	GENERAL ELECTRIFICATION WORK UNDER PWD B&R DIVISION NO.3 NAWA RAIPUR (UNDER PWD E/M SUBDIVISION RAIPUR	Rs 76.82 Lacs.
110/SE E/M/2024-2025 (1 Call) System Tender No 156759 Registered contractor class in "C" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	NIT SCHEDULE FOR PROVIDING GENERAL ELECTRIFICATION WORK TO SR/MOW/OW/ DEPOSIT IN GOVT RESIDENTIAL & NON RESIDENTIAL BUILDINGS & ROAD LIGHT WORK UNDER PWD (B/R) DIVISION GARIYABAND (C.G.)	Rs 128.00 Lacs
112/SE E/M/2024-2025 (1Call) System Tender No 156778 Registered contractor class in "D" & above For Form "A" (Percentage Rate Tender)	PROVIDING GENERAL ELECTRIFICATION WORK under district hospital section DKS hospital SR/MOW/ OW/DEPOSIT FOR NON RESIDENTIAL BUILDINGS C.E. Office UNDER DKS(M) UNDER SUBDIVISION RAIPUR (C.G.)	Rs 43.85 Lacs

Note: last date of bid submission of NIT will 13-08-2024
The tender documents can be downloaded from the web-portal http://eproc.cgstate.gov.in.Only those contractors/bidders, interested in bidding shall pay the tender document cost online.

**Superintending Engineer
P.W.D., E/M Circle Raipur (C.G.)**

G- 242501498/10

अखिलेश ने किया अपना पुनराविष्कार

प्रभु चावला

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक महान पहलवान थे। वे चरखा दांव में माहिर थे, यानी प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देने की कला। उन्होंने समाजवादी पार्टी बना उत्तर प्रदेश के जोखिम भरे राजनीतिक अखाड़े में भी बड़ी कुश्तियां जीतीं। उनके बेटे अखिलेश यादव ने स्टारडम का राज समझ लिया है- 141 करोड़ भारतीयों और 543 सांसदों द्वारा देखा और सुना जाना। कई युवा सांसद अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए दोस्त बना रहे हैं। अखिलेश सिर्फ एक सांसद नहीं हैं- वे एक मुख्यमंत्री थे। जंतर-मंतर पर एनडीए के खिलाफ क्षेत्रीय दलों द्वारा आयोजित धरने पर बैठकर अखिलेश ने यह साबित कर दिया कि क्षेत्रीय ही राष्ट्रीय है। उन्हें आंध्र प्रदेश के अपदस्थ मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आमंत्रित किया था, जिन्होंने आगाह किया था कि उनकी वाईएसआर कांग्रेस के पास संसद में कुल 15 सांसद हैं और एनडीए सरकार, जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू भागीदार के रूप में शामिल हैं, को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह और अखिलेश शायद ही कभी सामाजिक या राजनीतिक कारणों से मिले हों। फिर भी, यादव जूनियर ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अखिलेश उत्तर भारत से परे अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और 2029 तक सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। विचारधारा के रूप में समाजवाद कालबाह्य हो चुका है, लेकिन राजनीति में समाजीकरण विपक्ष की रणनीति है। अखिलेश एक युवा नेता हैं, जो जाति कार्ड नहीं खेलते हुए और मुलायम के लोहियावादी बोझ के बिना आधुनिक सोच रखते हुए खुद को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों के साथ सपा को शानदार जीत दिलाई है और 18वीं लोकसभा में वह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तब से वे अपनी पार्टी के अंदर और बाहर बहुत सक्रिय हैं। अब वे एक शांत स्वभाव वाले योद्धा नहीं रह गए हैं; वे व्यंग्य, काव्य और शोध से परिपूर्ण गंभीर भाषण देते हैं। वे विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और अपने घर या संसद के बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दिल्ली में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वैकल्पिक कथानक पर हावी होने के लिए सपा की भावी रणनीति की योजना बनाने के लिए अपने संसदीय दल की बैठकें कीं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक बैठकें भी कीं। वह अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ लोकसभा में जाते हैं और अपने देश के लिए अच्छे इरादों वाले एक आकर्षक राजनीतिक जोड़े की छवि प्रस्तुत करते हैं। वह संसदीय एजेंडे को प्रभावित करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वह कभी भी किसी सामाजिक मेलजोल से नहीं चूकते। यूपी से बाहर यात्रा करते समय, वह ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इनपुट और जानकारी दे सकते हैं। इस साल उन्होंने कोलकाता, पटना, चेन्नई और मुंबई का दौरा किया। यह राजनीतिक शैली में एक बड़ा बदलाव है। पिछले एक दशक में अखिलेश ने खुद को लखनऊ तक ही सीमित रखा था और ज्यादातर करीबी विश्वासपात्रों से ही मिले, घर से सिर्फ पार्टी मीटिंग के लिए निकले। बाकी समय उन्होंने परिवार के साथ बिताया, घर के पिछवाड़े में फुटबॉल या क्रिकेट खेला। अब, कई सालों के बाद, भारत एक नए युवा क्षेत्रीय क्षत्रप को देख रहा है जो राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए बेताब है। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव मोटे तौर पर अपने गृह राज्यों में ही रहे हैं, जबकि अखिलेश दिल्ली में अपने सांसदों के साथ घुलमिल गए हैं। अखिलेश का लक्ष्य सपा को समावेशी मंच में बदलना और शीर्ष पर पहुंचना है। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक शैली में बदलाव किया और दागी छवि वालों को बाहर निकालकर अपनी खुद की पार्टी बनाई। उन्होंने भारत में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ विदेशी संस्थान से भी पर्यावरण इंजीनियरिंग में डिग्री पाई है और पर्यावरण प्रबंधन की कला में महारत हासिल की है। अखिलेश ने अपने पिता के एमवाय (मुस्लिम और यादव) के राजनीतिक गठबंधन के बजाय एक नया नारा गढ़ा, पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक)। पीडीए एक गेम-चेंजर था - इसने 2024 में सपा को पांच सांसदों से 37 तक पहुंचा दिया। उम्मीदवारों की सूची में गैर-यादव बहुमत में थे। पूंजीवादी मूल्यों के साथ उदार और मानवीय, जैसा कि सीएम के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है।

ममता पर राहुल की मेहरबानी से हो गई कुर्बानी

अभिनय आकाश

साल 2007 की बात है प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और दिल्ली के अशोका होटल में सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया। वैसे तो इस डिनर का मुख्य मकसद सांसदों की प्रतिभा पाटिल से मुलाकात कराना था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियरंजन दास मुंशी के साथ बैठे एक नेता का परिचय सोनिया गांधी ने 'टाइगर ऑफ बंगाल' के रूप में कराया। वो नाम है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता ने खुली बगावत कर दी है। जिससे पार्टी में रार पैदा हो गई है। हद तो तब हो गई जब इस नेता ने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए। वहीं राहुल गांधी पर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बीजेपी जमकर मजे ले रही है। दिग्गज नेता के बागी होते ही बीजेपी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि गांधी परिवार को जबतक किसी नेता की जरूरत होती है तब तक वो उसे खूब पुचकारते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब पूरा हो जाता है वैसे ही उसे किनारे लगा दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति सुधारकर भी नर्वस 99 का शिकार होने वाली कांग्रेस को फिलहाल अपना घर संभालने में दिक्कत आने लगी है। पार्टी के बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से साफ कह दिया है कि वो अपने साथियों के साथ सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन की राह पर रहेंगे लेकिन अन्याय से समझौता नहीं करेंगे।

17वीं लोकसभा में कांग्रेस के सदन के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी इस वक्त पार्टी में अलग थलग हो गए हैं। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। उसके बाद कांग्रेस आलाकमान पर अधीर रंजन का गुस्सा फूट पड़ा है। अधीर ने फेसबुक पर पोस्ट कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं है। अधीर रंजन उन मुखर राजनेताओं में रहे हैं जो खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं। आज भी वो अपनी बात पर अड़ गए हैं। लेकिन उनकी बात न तो राहुल गांधी सुन रहे हैं और न ही सोनिया गांधी। हालांकि

एक बार सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात जरूर की लेकिन उसके बाद से अधीर रंजन के बार बार गुहार लगाने के बावजूद सोनिया ने उनसे मुलाकात नहीं की। अधीर ने हमेशा से टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग से लेकर किसी भी तरह से गठबंधन का विरोध किया। आखिर में उन्हें बहरामपुर से यूसूफ पठान से हार मिली।

दिल्ली में कांग्रेस ने प्रांतीय नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक से ये साफ हो गया कि अधीर रंजन प्रांतीय अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत किसी भी नेता ने उन्हें पहले से कुछ नहीं बताया। अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही भेज दिया था, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया था कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं।

अधीर के फेसबुक पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अधीर रंजन ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि हमारे लोग पिट रहे हैं, कार्यकर्ता दिन-रात जमीनी स्तर के हाथों पिट रहे हैं, उनके लिए हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? सत्ताधारी जमीनी स्तर के लोग हर दिन हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं! %इंडिया% गठबंधन में शामिल होकर उन्होंने हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया! तृणमूल इस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है, क्या उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बख्शा है? आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, झूठे मुकदमों में दबे हुए हैं, हमारे पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है, कोई रोक नहीं रहा! तो फिर मैं जमीनी स्तर के लोगों के खिलाफ कैसे चुप रह सकता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह मेरे सहयोगियों के साथ अन्याय होगा! मैं नहीं कर सकता। दिल्ली को उन कार्यकर्ताओं से भी बात करनी चाहिए जो दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी राय भी जाननी चाहिए। उन्हें भी दिल्ली बुलाने की जरूरत है। मैं अपने उन सभी साथियों के साथ सड़कों पर रहूँगा, आंदोलन पथ पर रहूँगा, जिन्होंने अन्याय से समझौता करना नहीं सीखा है और न सीखेंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद प्रदेश से कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया। वहीं इसका ठीकड़ा अधीर रंजन के ऊपर फूटा। लेकिन अधीर रंजन के तेवर भी बगावती नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन के समर्थकों का तर्क है कि सोमेन मित्रा के निधन के बाद उन्हें प्रदेश में कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। पार्टी उस वक्त विधानसभा में दूसरे नंबर पर थी। लेकिन 2021 के बंगाल विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी से अलग होकर चुनाव लड़ा लेकिन जमीन पर ऐसा दिखा नहीं। न तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रदेश में प्रचार करने आया और न ही ममता सरकार के कार्यकाल को लेकर कोई टिप्पणी की गई। इसका असर ये होता दिखा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के वोटर भी जमीन पर मजबूत ममता की ओर शिफ्ट हो गया। दावा ये भी किया जा रहा है कि अधीर रंजन अध्यक्ष पद पर अपने किसी करीबी को कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। लेकिन पार्टी हाई कमान ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाना चाहती है। ऐसा व्यक्ति जो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी बेहतर तालमेल कायम कर सके। कांग्रेस जहां एक तरफ ममता के साथ ही राज्य में अपने भविष्य को देख रही है। वहीं अधीर एकला चलो रे वाली नीति की पैरवी कर रहे हैं।

अधीर रंजन के बागी तेवर के बीच उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हो चली हैं। तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही बीजेपी से बात कर रखा है। कुणाल घोष ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से निलंबित होना चाहते हैं। वह उकसाने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि उन्होंने पहले ही बीजेपी से बातचीत कर रखा हो। रिपबल्किन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने अधीर रंजन को तो एनडीए में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से हारने की वजह से ही उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मैं अधीर रंजन जी से गुजारिश करता हूं कि अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। रामदास आठवले ने कहा कि मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी ऋह्ह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

वैसे कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी का रूख फ्लिप-फ्लॉप वाला रहा है। पहले तो इंडिया गठबंधन की बैठकों में सीटों के बंटवारे पर जोर दिया। फिर अचानक कांग्रेस की हैसियत 2 सीटों से ज्यादा की नहीं बताई है। आलम ये हो गया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बंगाल पहुंचने से पहले ही बंगाल में ममता बनर्जी ने गठबंधन तक करने से मना कर दिया। अधीर रंजन इस दौरान ममता बनर्जी पर तल्ख जरूर नजर आए। लेकिन आलाकमान यानी राहुल, सोनिया, खरगे की तरफ से उनको लेकर कोई तीखे बयान सामने नहीं आए। चुनावी नतीजे के बाद फिर से ममता पहले इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन और यू टर्न लेकर इंडिया ब्लॉक में ही रहने की बात करती नजर आईं। प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर भी ममता ने अलग राह अपनाते हुए विपक्ष के समर्थन पत्र पर साइन नहीं किया। बाद में कहा जाता है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी की फोन पर बात भी हुई। लेकिन हालिया नीति आयोग की बैठक को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और टीएमसी का स्टैंड बदला नजर आया। कांग्रेस समेत कई दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया तो टीएमसी नेता इस बैठक में पहुंच गई।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-8)

गतांक से आगे...

मानव सृष्टि में प्राणियों की गति-विधियों का तारतम्य ही जन्म-मरण विधायक है, उसके परिज्ञानार्थ औौर्ध्वदैहिक रहस्य निरूपण करने वाला छठा गरुडपुराण है। यहां तक यह व्यञ्जित हो चुका कि बह नाभि-कमलस्थ ब्रह्मा, वेदात्मक-ज्ञान, लिङ्गात्मक कारणीभूत पदार्थ और जीवों की कर्म-परम्परा के अनुसार ही सर्वोन्मुख हुआ। तब सब से पूर्व विमिश्रित पञ्चमहाभूतों का कलाल जिसे वैदिक भाषा में उच्छिष्ट, पौराणिक भाषा में नार और स्मृति शब्दों में आप कहते हैं उत्पन्न, हुआ।

अप एवं ससर्जादौ (मनु 1।8) आपो नारा इति प्रोक्ता: (मनु 1।10) आदि प्रमाण इस विषय में द्रष्टव्य हैं। इस भाव को प्रकट करने वाला सातवाँ नारदपुराण है। नर (कारणजलों) का दाता होने के कारण यही तत्त्व नारद है।

अनन्तर यह पंचमहा- भूतात्मक अण्डाधिष्ठित देव द्यौ: भूमि अथवा पुरुष-स्त्री नाम दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसका ऐश्वर्यादि पड्गुण युक्त दक्षिणांश भगवान् और वामांश भगवती कहा जाता है, इस तत्त्व को प्रकट करने वाला आठवाँ पुराण भगवती है, ओ पुरुष प्राधान्य से श्रीमद्भागवत और प्रकृति प्राधान्य से देवी भागवत के नाम से विख्यात है।

यहाँ से वैजी- सृष्टि का आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार विष्णु से आरम्भ करके मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति-पर्यन्त तात्त्विक पौर्वापर्य का क्रम दिखाया गया है। अब स्वभावत: यह जिज्ञासा होगी कि पूर्वोक्त रीति से जन्म मरण के बन्धन में फंसे हुवे जीव का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? इसका समाधान अगले पुराणों में किया गया है। नवम पुराण अग्नि द्वारा यज्ञादि सकाम कर्म करके शुभ लोकों की प्राप्ति का आदेश करता है।

क्रमश: ...

पंडित रविशंकर शुक्ला

2 अगस्त 1877 को जन्मे रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर जिले में हुआ था, उनके पिता का नाम जगन्नाथ शुक्ला था। रविशंकर शुक्ला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सागर में ही पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की इस दौरान उनके शिक्षा दीक्षा रायपुर जबलपुर और नागपुर से संपन्न हुई। शि क्षा समाप्त करने के बाद 3 साल तक खैरागढ़ राज्य के हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक और बस्तर कवर्धा एवं खैरागढ़ के राजकुमारों के शिक्षक रहे। साल 1906 में रायपुर में वकालत की शुरुआत की। पंडित रविशंकर शुक्ल ने वकालत की पढ़ाई के दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलन के करीब जुड़ चुके थे।

शुरू से पण्डित रविशंकर शुक्ल सार्वजनिक कार्यों पर रूचि रखते थे। लेकिन देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन शुरू होने के दौरान ही उन्होंने वकालत छोड़ कर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथी राजनीति के क्षेत्र में भी उतर आए। आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 1930 में पंडित रविशंकर शुक्ल को 3 साल की सजा हुई। पंडित रविशंकर शुक्ला एक कानूनी विद्वान के साथ-साथ एक उत्कृष्ट अनुभवी नेता थे। वह एक प्रतिबंध लोकतांत्रिक और देशभक्त थे। जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

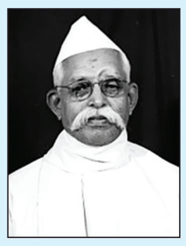

पंडित रविशंकर शुक्ला स्वराज पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। सन 1926 से 1937 तक वह रायपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे। 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 4 जुलाई, 1937 ई। को खरे के प्रथम कांग्रेसी मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्रि के रूप में सम्मिलित हुए तथा विद्या मंदिर योजनाओं को क्रियान्वित किया। दो साल पहले 1935 में मध्यप्रांत और बरार मिलाकर एक कर दिए गए थे। तो खरे ऐसे इलाके के प्रधानमंत्री हुए थे जहां तीन अलग-अलग तासीर के इलाके थे - विदर्भ, महाकोशल और बरार। शुक्ल 15 अगस्त, 1947 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1956 तक वे इस पद पर बने रहे। 1 नवंबर, 1956 को नए मध्य प्रदेश के प्रथम संस्थापक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

कांग्रेस 1957 के विधानसभा चुनाव के लिए शुक्ल का टिकट काटने का पूरा मन बना चुकी थी। 78 साल के शुक्ल के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। अब शुक्ल लौटना चाहते थे। लेकिन जाते कहां। तब दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन नहीं बना था। मध्यप्रदेश के नेता दिल्ली में कोटा हाउस में ठहरते थे। लेकिन शुक्ल का मन लगता था 3 केनिंगलेन पर। ये उनके दोस्त सेठ गोविंददास को बतौर सांसद मिला सरकारी बंगला था। वहीं चले गए। इसी घर में अगले दिन माने 31 दिसंबर, 1956 को दोपहर 11 से 12 के बीच किसी घड़ी शुक्ल को दिल का दौरा पड़ा और वो शांत हो गए। दोपहर देढ़ बजे ऐलान किया गया कि देश के सबसे बड़े राज्य के पहले मुख्यमंत्री पं रविशंकर शुक्ल नहीं रहे। मध्यप्रदेश शासन की सील पर आज भी बरगद का निशान है। शुक्ल की कहानी जानने वाले उस बरगद को देखकर उन्हें ही याद करते हैं।

विदेश नीति और राज्यों के दायरे

डॉ. धनंजय त्रिपाठी

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विदेशी मामले, रक्षा और मौद्रिक नीति से संबंधित अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। हाल में केरल सरकार द्वारा एक 'विदेश सचिव' की नियुक्ति के बाद इस मसले पर बहस चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े भारत और बांग्लादेश के बीच किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगी। उनका कहना है कि ऐसे समझौते से उत्तर बंगाल के लोगों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल सकेगा। केरल सरकार ने सचिव की नियुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि विदेशी एजेंसियां, दूसरे देशों में दूतावासों से संबंधित संस्थान आदि केरल और अन्य राज्यों की सरकारों के नियमित संपर्क में रहती हैं। केरल सरकार ने कहा है कि इस अधिकारी को राज्य के विकास के लिए संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में कई राज्य सरकारें दूसरे देशों की सरकारों से संपर्क रखती हैं। इसके अनेक कारण हैं। एक तो विदेशों में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती गयी है। जो लोग देश से बाहर हैं, उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों की भी होती है। दूसरी वजह यह है कि राज्य सरकारें अपने यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों के संपर्क में रहती है तथा इस संबंध में प्रचार-प्रसार भी करती हैं। तीसरा कारण है विदेशी और अनिवासी भारतीयों का निवेश।

बीते वर्षों में हमने देखा है कि कई राज्य सरकारें अपने यहां समय-समय पर निवेशकों के सम्मेलन आयोजित करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'वाइब्रेंट गुजरात' सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत 2003 में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। राज्य में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक विदेश यात्राएं की थीं। साल 2011 में जब वे चीन गये थे, तो उन्होंने चीनी जेलों में बंद गुजरात के लोगों का मुद्दा उठाया था। साल 2015 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू लगभग 40 लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर चीन गये थे। यह प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री का चीन दौरा प्रस्तावित था। नायडू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के दौरे की रूप-रेखा तैयार करने में भी योगदान दिया था। साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह पूर्वोत्तर के चार मुख्यमंत्रियों को लेकर बांग्लादेश गये थे। ये उन राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है।

भारत-बांग्लादेश भूमि समझौता एक बहुत कारगर और सफल समझौता है। उसे साकार करने में बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हालिया बातें जो हुई हैं, वे नयी नहीं हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका में आंध्र प्रदेश के एक युवक की हत्या हो गयी थी, तो राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय से उसका शव लाने तथा अन्य सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया था। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में पढ़ रहे कई भारतीय छात्रों को निकाला गया था। ये छात्र विभिन्न राज्यों से थे। वहां की सरकारों ने केंद्र सरकार से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित लाने का आग्रह किया था।

अक्तूबर 2014 से विदेश मंत्रालय में एक विभाग चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की होती है। इस स्टेट डिवीजन का दायित्व राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों एवं उच्चायोगों के साथ संपर्क स्थापित करना है। इस विभाग का उद्देश्य भी प्रवासियों की देखभाल, निवेश और पर्यटन विकास है। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब अक्सर कहा करते थे कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने यहां अधिक निवेश ला सकें। इस तरह की बातें भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में भी उल्लिखित होती थीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक अवधारणा 'पारा-डिप्लोमेसी' की है। यह अवधारणा यही कहती है कि विदेश संबंध विकेंद्रित भी हो सकते हैं तथा राज्य सरकारें अपने देश के दूतावासों के साथ समन्वय स्थापित कर निवेश ला सकती हैं तथा विदेशी मामलों में सकारात्मक सहयोग कर सकती हैं। ऐसी व्यवस्था को एक तरह की कूटनीति कहा गया है। अभी जैसी व्यवस्था केरल में की गयी है, वैसी ही व्यवस्था हरियाणा में भी है। केरल सरकार ने कहा है कि उक्त अधिकारी का काम विदेश मंत्रालय से संपर्क का ही है। यह भी स्थापित तथ्य है कि बड़ी संख्या में केरल के लोग दूसरे देशों में कार्यरत हैं। मेरा मानना है कि इसे विदेशी मामलों में किसी तरह के हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा हस्तक्षेप संभव भी नहीं है क्योंकि विदेश मामले केंद्र सरकार का विषय हैं और यह संविधान में रेखांकित किया गया है।

किसी भी संघीय व्यवस्था में विदेश नीति केंद्र के अधीन ही होती है, पर जिस तरह की वैश्विक चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से वैश्वीकरण होता जा रहा है, तो राज्यों को भी संपर्क बनाने की आवश्यकता बढ़ती गयी है। हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे देशों के राज्यों के प्रशासक और बड़े शहरों के मेयर अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत आते हैं। हमारे यहां से भी मुख्यमंत्री और मंत्री आधिकारिक दौरे पर अन्य देशों की यात्रा करते हैं। ऐसी यात्राएं विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावासों के सहयोग से ही संभव होती हैं। केरल के इस कदम से यह अवश्य हुआ है कि संपर्क व्यवस्था को उसने संस्थागत रूप दे दिया है। हमारे देश में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। कई कंपनियां और विदेशी कार्यरत भी हैं। हवाई अड्डों का नेटवर्क बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कंपनियां राज्य सरकारों के संपर्क में रहती हैं। विकास के साथ-साथ सभी चीजों को केंद्रीकृत व्यवस्था से ठीक से चला पाना आसान नहीं होता। निवेश को ही देखें, तो राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है। राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के छूट और सुविधाओं को प्रस्तावित करते हैं। आने वाले समय में राज्यों की सक्रियता में बढ़ोतरी ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ऐसी कोशिशों और संपर्कों के समर्थक रहे हैं। इससे केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे संविधान द्वारा दिये अधिकार हैं तथा इसका अहसास राज्य सरकारों को भी है। जहां तक ममता बनर्जी के बयान का सवाल है, तो वह मुद्दा पानी जैसे संवेदनशील विषय से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस पर बातचीत कर और उन्हें भरोसे में लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए।

आज का इतिहास

1981 मोहम्मद अली राजई को ईरान के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

1984 यूरो अदालत फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध खड़ी हो गयी।

1986 स्टूडियो गबिली द्वारा निर्मित पहली फिल्म, हाओ मियाज़ाकी द्वारा निर्देशित कैसल इन द स्काई जापान में जारी की गई।

1990 इराक ने कुवैत पर हमला किया, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय निंदा की गयी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा इराक के खिलाफ तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध लागू किया गया।

1990 एक तेल झगड़े के कारण 100,000 इराकी सैनिकों ने कुवैत पर आक्रमण किया। सद्दाम हुसैन, इराकी तानाशाह ने कुवैत शहर को कब्रिस्तान में तब्दील करने की धमकी दी, अगर कोई अन्य देश बलपूर्वक आक्रमण के खिलाफ विरोध करने की कोशिश करता है।

1990 इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैत के सैन्य युद्ध के दिनों को पलट दिया और आखिरकार सात युद्ध के बाद खाड़ी युद्ध का प्रकोप बढ़ा।

1999 चीन ने 8000 किमी की लम्बी दूरी तक हमला करने वाली की मिसाइल का परीक्षण किया जो सतह से सतह पर मारने की क्षमता रखती।

2003 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाइबेरिया में हुवे संघर्ष को रोकने के लिए के लिए सेना भेजने की अनुमति दी।

2004 अमेरिका की लिंडसे डेवनपोर्ट ने रूस की मिस्कीनी की हराकर सान डियागो टेनिस चैम्पियनशिप का महिला एकल ख़िताब जीत लिया।

2007 अल कायदा और तालिबान समर्थकों में से दो को पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर दोषी ठहराया गया है।

2008 जाफना के दक्षिणी द्वीप कियुशु में सुबह भयानक तूफ़ान आ गया जिसने उगासी ने व्यापक पैमाने पर वह तबाही मचाई।

2008 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एंटोनियो पेटीग्रेव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 4 म 400 मीटर रिले टीम को उनके स्वर्ण पदक से हटा दिया है, टीम के सदस्यों में से एक ने डोपिंग की बात कबूल की है।

2009 मंगोलिया के कम्युनिस्ट निष्कासन के दौरान 1930 के दशक में दफन किए गए असामान्य बौद्ध सामान गोबी रेगिस्तान में पाए जाते हैं।

धर्म परिवर्तन की रोकथाम के लिए योगी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

डॉ. सौरभ मालवीय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जनहित में बड़े एवं ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद के विरुद्ध नए विधेयक को पारित करवाकर एक और इतिहास रच दिया है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तभी से वे भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अपनी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है तथा वह इसी का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं।

विगत दीर्घ काल से लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं। प्रकरणों के अनुसार प्रेम प्रसंग में पड़कर लड़कियां दूसरे धर्म के पुरुषों से विवाह कर लेती हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात् इन लड़कियों पर ससुराल पक्ष का धर्म स्वीकार करने का दबाव बढ़ने लगता है। बहुत सी लड़कियां ससुराल पक्ष का धर्म स्वीकार करने पर विवश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। जो लड़कियां ऐसा नहीं करतीं, उनका जीवन नारकीय बन जाता है। उन्हें ससुराल में यातना एवं अपमान का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकरणों में पति अथवा ससुराल पक्ष द्वारा लड़कियों को बेच देने के मामले भी प्रकाश में आए हैं। ऐसे प्रकरणों में लड़कियों की हत्याओं के मामले भी प्रकाश में आए हैं। निन्संदेह ऐसे प्रकरण किसी भी सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।

अब उत्तर प्रदेश में नया कानून बनने से कुछ संतोषजनक होने की आशा जगी है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद की रोकथाम के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन एवं लव जिहाद के विरुद्ध नया विधेयक प्रस्तुत किया, जो मंगलवार को पारित हो गया। इसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 नाम दिया गया है। इस नए विधेयक के अनुसार नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने तथा उसे बेचने पर आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार सामूहिक रूप से जबरन धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान है।

ऐसे प्रकरण भी सामने आते रहते हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से भारी मात्रा में धनराशि आती है। योगी सरकार की दूरदर्शिता के कारण अब इस पर भी रोकथाम लग सकेगी। इस विधेयक में विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए आने वाले धन पर भी अंकुश लगाने हेतु कठोर प्रावधान किए गए हैं। विदेशी अथवा अपंजीकृत संस्थाओं से धन प्राप्त करने पर 14 वर्ष तक का कारावास तथा 10 लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन अथवा उसकी धन-संपत्ति को भय अथवा हानि में डालता है, उस पर बल प्रयोग करता है, उसे विवाह का झांसा देता है, लालच देकर किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बेचता है, तो उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। दोषी को पीड़ित के उपचार एवं पुनर्वास के लिए भी आर्थिक दंड चुकाना होगा। अब जबरन धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। इससे पूर्व केवल पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवारजन अथवा संबंधी ही प्राथमिकी दर्ज करवा सकते थे। इस प्रकार योगी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने की दिशा में प्रथम पग उठा लिया है। अब इस विधेयक को विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद भेजा जाएगा। तत्पश्चात इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके पश्चात् इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व नवंबर 2020 में योगी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। इसके पश्चात् फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम- 2021 अस्तित्व में आया था। इस विधेयक के अंतर्गत दोषी को एक से 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान था। इस विधेयक के अंतर्गत केवल विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन ही अमान्य था। किसी से झूठ बोलकर अथवा उसे धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया था। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे दो माह पूर्व मजिस्ट्रेट को सूचित करने का प्रावधान था। विधेयक के अनुसार जबरन अथवा धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपए आर्थिक दंड के साथ एक से डेढ़ वर्ष के कारावास का प्रावधान था। यदि दलित लड़की का धर्म परिवर्तन होता है तो 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड के साथ तीन से 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान था।

उल्लेखनीय है कि जबरन धर्मांतरण के दृष्टिगत देश के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू हैं। इनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा सम्मिलित हैं। महाराष्ट्र में भी जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध विधेयक लाने की बात कही जाती रही है, किंतु इस संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है।

पूर्व के कानून की तुलना में नए कानून को अधिक सशक्त एवं कठोर बनाया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लव जिहाद के प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिन्दुत्ववादी संगठन लम्बे समय से कठोर कानून की मांग करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि कठोर कानून से ही उनकी बहन-बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो लव जिहाद को 'मिथ्या' की संज्ञा देता है। इस वर्ग का कहना है कि देश में 'लव जिहाद' नाम की कोई चीज नहीं है। प्रश्न यह भी है कि यदि ऐसा है तो फिर यही वर्ग इस प्रकार के कानूनों की आलोचना क्यों करता है?

वास्तव में यह विधेयक किसी समुदाय या वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं है, अपितु यह केवल जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है- कानून में जो संशोधन और सुधार हो रहा है उसके पीछे यह मकसद है कि और कड़ाई से नियम लागू हों और इस तरह की चीजें न हो। विपक्ष जो कह रहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यह कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, वे इसका विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे और उन्हें वोट देता रहे, वे सरकार बनाते रहें और मुसलमानों को धोखा देते रहें।

कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम धर्म नहीं देखता है। यदि प्रेम की बात की जाए, तो प्रेम त्याग का दूसरा रूप है। प्रेम की बात करने वाले लोगों को त्याग के नाम पर सांप सूंघ जाता है। यह कैसा प्रेम है, जो केवल लड़की से उसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान छीन लेता है। यदि पुरुष इतना ही प्रेम करने वाला है, तो वह लड़की का धर्म स्वीकार क्यों नहीं करता? यह कैसा एक पक्षीय प्रेम है? प्रेम के नाम पर धोखा, छल और साजिश तो नहीं ?

हरियाणा चुनाव से तय होगी 'आप' की राजनीति

अमित शर्मा

अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अंतिम चार्जशीट अदालत में फाइल कर दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी उनकी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल का मुद्दा लोगों के बीच ले जाने की कोशिश भी कर रही है, जिससे वह इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। संभवतया इस समय उसके पास यही सबसे मजबूत मुद्दा भी है, जिसके सहारे वह जनता से समर्थन की उम्मीद कर सकती है। लेकिन क्या वह अपनी रणनीति में सफल हो सकेगी? लोकसभा चुनाव के पूर्व इसी मुद्दे पर आप की यही रणनीति उसके लिए बहुत सुखद परिणाम लाने में नाकाम साबित हुई थी। मंगलवार 30 जुलाई को आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और यह दिखाने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल उसके साथ हैं। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने एक सुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया और केजरीवाल का साथ देने की बात भी कही। इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव, शरद पवार, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और वामपंथी दलों के नेता शामिल थे। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के ही रामलीला मैदान में भी इसी तरह विपक्षी दलों को साथ लाने का काम किया था। वह रैली इंडिया गठबंधन की तरफ से आयोजित की गई थी, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी यह संदेश देने में सफल रही थी कि सभी विपक्षी दल उसके साथ खड़े हैं। हालांकि, वह रैली जिस दिल्ली की लोकसभा सीटों को ध्यान में रखकर बुलाई गई थी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस उनमें से एक सीट पर भी सफलता पाने में असफल रही थी। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा प्रश्न यही है कि जब अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने के बाद भी लोकसभा चुनावों में पार्टी को कोई सफलता नहीं दिला सके, तो उनके न रहने के बाद आम आदमी पार्टी उनके नाम को कितना भुना सकेगी। दूसरी बड़ी समस्या यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने इसके पहले भी हरियाणा में चुनाव प्रचार भले ही किया हो, लेकिन उनके लिए मुख्य कर्मभूमि दिल्ली ही रही है। यदि दिल्ली में उनके नाम का कोई असर नहीं हुआ तो हरियाणा में उनके प्रति कितनी सहानुभूति हो सकेगी? अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग-अलग चुनाव मैदान में होंगे, तो उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, इस पर बहस की जा सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को आगे रखकर दिल्ली वाली गारंटी दोहरा रही है। मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर शिक्षा के उसके वादे तभी लोगों को प्रभावित कर पाएंगे जब पार्टी का मजबूत नेतृत्व पूरे दमखम के साथ उसे जनता के बीच पहुंचाने में सफल रहे। लेकिन हरियाणा में संगठन की कमजोरी के साथ-साथ उसके पास स्थानीय स्तर पर बड़े नेता भी नहीं हैं, जो उसकी बात को जनता तक ले जा सकें। ऐसे में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक साथ कई चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की भूमिका को हथिया कर ही आगे बढ़ी है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस बेहद मजबूत भूमिका में है। उसके स्थानीय नेता बहुत मजबूत स्थिति में हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता हरियाणा में काफी है। ऐसे में यदि जनता बदलाव का मन बनाती है, तो इसके लिए जनता की पसंद कांग्रेस हो, इसकी संभावना ज्यादा हो सकती है। इससे आम आदमी पार्टी का संकट ज्यादा बड़ा हो सकता है। भाजपा नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। उसका दिल्ली मॉडल दिल्ली में ही बुरी तरह असफल साबित हुआ है। स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को मोहल्ला क्लीनिक दिया गया था, लेकिन यह सामने आ चुका है कि किस तरह मोहल्ला क्लीनिक में एक ही नाम और फोन नंबर पर हजारों लोगों के इलाज का फर्जी दावा किया गया।

जनगणना से कब तक डरना

अरविन्द मोहन

बजट से जुड़ा हलवा बांटने वाले और हलवा खाने के रूपक के सहारे बात को जातिगत जनगणना तक ले जाने वाले राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चल दी। अब इसका कितने लोगों पर कैसा असर हो रहा है इसका हिसाब अलग-अलग हो सकता है, लेकिन भाजपा पर इसका प्रभाव काफी पड़ा है। उसकी तरफ से राजनीति को हिन्दू-मुसलमान लाइन पर ले जाने का प्रयास बंद नहीं हुआ है लेकिन अब वह हर बात में जाति के सवाल को महत्व देने लगी है और राहुल गांधी तथा कांग्रेस को ही नहीं समाजवादी पार्टी और राजद को ही पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से वह जातिगत जनगणना के खिलाफ है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानती-भले उसने बिहार में हुई जातिगत जनगणना का समर्थन किया था।

लेकिन राहुल गांधी को अपनी इस राजनीतिक रणनीति या भाजपा की घेराबंदी में एक बार भी याद नहीं आया कि देश में वह सामान्य जनगणना भी नहीं हुई है जो विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं रुकी थी। और सरकार ने जिस कोरोना के नाम पर जनगणना रोकी थी (हालांकि दुनिया में ऐसा सिर्फ 2 अन्य देशों में ही हुआ था) उसे गए जमाना हो गया है और अब आम चुनाव समेत सब काम रुटीन पर लौट आया है। विपक्ष का नेता होने के चलते राहुल को यह पूछने की जरूरत थी क्योंकि इस बजट में भी जनगणना के लिए धन का प्रावधान नहीं हुआ है-यह रकम पहले से कम कर दी गई है।

और तब भले गृहराज्य मंत्री ने सदन में और गृह मंत्री ने बाहर कोरोना के चलते जनगणना रोकने और ज्यादा व्यापक सवालों के साथ जनगणना कराने की बात कही हो अब तो सरकार के अधिकारी कहने लगे हैं कि 1948 के जनगणना कानून में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि हर 10 साल पर अनिवार्य रूप से जनगणना हो ही। संभवत ऐसा है भी लेकिन पिछले डेढ़ सौ साल की जनगणना की परंपरा और उसकी रोजाना के काम की उपयोगिता ने हमारे लिए कानून के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं छोड़ी थी।

चुनाव के क्षेत्र निर्धारण से लेकर सरकारी नीतियां बनाने और संसाधनों के आबंटन तथा आगे होने वाले हर सर्वेक्षण में जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने की आदत हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह समा गई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छे दिन लाने और देश को विकसित दुनिया की बराबरी पर लाने और विश्व गुरु बनाने के दावे करने वाली सरकार जनगणना रोक देगी। इस सरकार का आंकड़ों से 'बैर' अब छुपा नहीं है। उसने जाने कितने आंकड़े जुटाने का काम रोका है, कितने जुटे आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने दिया है, कितने ही दूसरे अनुमानों को झुठलाया है, जी.डी.पी. की गणना से लेकर न जाने किस-किस हिसाब का आधार ही बदल दिया है।

इन सबसे हमारे सारे आंकड़े संदेहास्पद हो गए हैं जबकि ब्रिटिश शासन काल से ही महा-सांख्यिकी लेखाकार के अधीन आंकड़े जमा करने की एक मजबूत व्यवस्था के अभी तक काम करते जाने के चलते दुनिया में हमारे आंकड़ों को बहुत सम्मान से देखा जाता था। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने जी.एस.टी. कर वसूली के निरंतर बढ़ते जा रहे आंकड़ों और कर वसूली बढने के आंकड़ों को सर्वजनिक करने पर रोक लगा दी। देश विदेश के विभिन्न संस्थानों द्वारा जैसे जैसे जुटाए आंकड़े जब सरकार के पक्ष में होते हैं तो उनका शोर मचाया जाता है वरना उनको खारिज कर दिया जाता है। और बुनियादी दिक्कत यह है कि जब 15 साल पुरानी जनगणना को रैंडम सैंपलिंग के लिए कितनी भी ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे गलत आने की पूरी गुंजाइश है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण हो या परिवार स्वास्थ्य या उपभोग सर्वेक्षण, सभी जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाते हैं। पर जनगणना का काम सिर्फ दूसरे सर्वेक्षणों का आधार बनना या उनकी पृष्ठभूमि तैयार करना नहीं है। उसका काम है देश की आबादी का, उसके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जीवन की वास्तविकता को सामने लाना। मकान की गिनती और स्थिति से शुरू होकर अब यह परिवार और व्यक्ति को लेकर बीसियों सूचनाएं जुटाता है और फिर उनको जमा करने के साथ वर्गीकृत करता है, विश्लेषित करता है। अगर अमित शाह की कुछ समय पहले कही बात अब भी सच है तो इस बार की जनगणना में कुछ और नई जानकारियां जुटाने का काम होना है।

इनके आधार पर ग्राम पंचायत और शहर के वार्ड से लेकर पंचायत और नगरपालिका, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का आकार-प्रकार बदला और तय किया जाता है। इनके आधार पर शहरी घोषित हो गए गांव और कस्बे में सुविधाओं और कायदे-कानून में बदलाव होता है। जिन आंकड़ों के आधार पर सरकार और स्वशासी संस्थाओं के बजट का आबंटन होता है। कई जानकारों का अनुमान है कि जिन पैमानों पर सरकार 81.5 करोड़ लोगों को आज मुफ्त राशन दे रही है अगर आबादी के नए हिसाब(अनुमान ही) को ध्यान में रखा जाए तो 93 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। अब राजनीतिक मजबूरी के चलते सरकार बिहार जैसे पिछड़े राज्य को जो धन दे रही है वह काम काफी पहले हो जाना चाहिए था।

इस बार की जनगणना रोकना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और सी.ए.ए. जैसे विवादास्पद प्रावधानों की उलझन के चलते हुआ है। इन 2 कानूनी प्रावधानों की जो दुर्गति हुई है सब देख रहे हैं। कुछ दर्जन केस भी सामने नहीं आए हैं। सरकार के डरने और जनगणना रोकने का कारण जातिगत जनगणना की मांग हो सकती है। राहुल ने वह काम तो नेता विपक्ष बनकर कर दिया है लेकिन जनगणना की मांग को छोड़ दिया।

संविधान की नौवीं अनुसूची और आरक्षण

केसी त्यागी/ बिशन नेहवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संबंधी मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि राज्य द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण ने 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को तोड़ने के लिए आवश्यक सामाजिक परीक्षण मापदंडों को पर्याप्त रूप से संतुष्ट किया है।

पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) संशोधन अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था और दोनों कानूनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव के खिलाफ अधिकार) और 16 (रोजगार में भेदभाव के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन माना था।

संविधान के अनुच्छेद 15(4) में, 'नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों व?अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान' करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 15 और 16 में महत्वपूर्ण शब्द %केवल% है-जिसका अर्थ है कि यदि कोई धार्मिक, नस्लीय या जाति समूह अनुच्छेद 46 के तहत 'कमजोर वर्ग' का गठन करता है, तो वह अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का हकदार होगा। इस विशेष प्रावधान का अर्थ मुख्यत: आरक्षण है। देश में आरक्षण को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। इसलिए कई राजनीतिक दल आरक्षण पर बार-बार होने वाले विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आरक्षण संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं।

बिहार में 65 फीसदी?आरक्षण, ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है। हालांकि, किसी कानून को नौवीं अनुसूची में रखने से उसे न्यायिक जांच से बचाया जा सकता है। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993, कॉलेजों और राज्य सरकार की नौकरियों में 69 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, जहां पर सबसे अधिक 69 प्रतिशत आरक्षण है और यह व्यवस्था संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा द्रविड़ आंदोलन प्रभुतासंपन्न समुदाय के खिलाफ शक्तिशाली भूमिधारक वर्गों का था, जो सत्ता के ज्यादातर?पदों पर काबिज थे। पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को लगा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने विभिन्न दलों?के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अंतत: आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करवाया। हालांकि वर्ष 2007 में नौवीं अनुसूची को भी चुनौती दी गई (आई आर कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य), लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से नौ न्यायाधीशों के आधार पर फैसला सुनाया कि नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्हें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 284 कानून न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं।

वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में 72 प्रतिशत का दायरा बढ़ाया था। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च कोटा प्रदान करने वाले दो संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ऐसे ही झारखंड सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था, जो राज्य में रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण बढ़ाकर 77 प्रतिशत करने से संबंधित था। हालांकि, यह भी विधेयक लागू नहीं हो सका और झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र से सिफारिश कि इस विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करें।

आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण नीतियों पर एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है, जैसे आरक्षण का दायरा खत्म करना और ईडब्ल्यूएस को जाति तटस्थ बनाना तथा सभी जातियों व वर्गों को इसमें शामिल करना आदि। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देश में कई तरह के सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष पैदा हो जाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर सोचने की जरूरत है।

जीईपी से पता चलेगा विकास की दौड़ में कितना खोया, कितना जोड़ा

अनिल प्रकाश जोशी

हाल के समय में देश और दुनिया में करीब 86 फीसदी लोगों ने प्रचंड गर्मी को झेला। इस गर्मी के पीछे समुद्र का बढ़ता तापमान और उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारक है। बीती 22 जुलाई अब तक का दुनिया का सबसे गर्म दिन था। समस्या यह है कि सही समय पर मौसम के मिजाज का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कब कहां किस रूप में बारिश हो जाए और कहां बाढ़ आ जाए और कब तूफान घेर ले, अब यह सब कुछ नियंत्रण से बाहर चला गया है। दरअसल, जीडीपी की दौड़ में कोई भी देश पीछे नहीं छूटना चाहता। जाहिर है कि जब-जब प्रकृति और पर्यावरण के सवाल खड़े होते हैं, तो सभी देशों का यही मानना होता है कि हम अपने हिस्से का विकास कैसे त्याग दें, जब दुनिया के बड़े-बड़े देश कहीं बेहतर स्थिति में खड़े हैं। विकास अपनी जगह है, लेकिन समस्या यह है कि देश-दुनिया की सरकारों ने कभी भी ऐसा लेखा-जोखा नहीं दिया, जिससे पता चले कि कितना खोया और कितना जोड़ा। उल्लेखनीय है कि हम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) जैसे सूचकांक को लाकर समझ सकते हैं कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में अभी कितना कार्य करना चाहिए। अमेरिका के एक मिस्टर साइमन थे, जिन्होंने 1935 से 40 के बीच में जीडीपी का विचार दिया था और उनका मानना यह था किआर्थिक वृद्धितथा विकास को मापने का बेहतर मापदंड जीडीपी है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इसको संपूर्ण सूचक न माना जाए। उनका इशारा साफ था कि जीडीपी प्रकृति के हालात की सूचक नहीं हो सकती। 2010 में एक विचार उठा कि सरकारें जंगल जोड़ने और हवा-मिट्टी-पानी को बेहतर करने के लिए भी कटिबद्धहैं और वे ऐसा करती भी हैं, लेकिन वह कितनाकर पाईं,उसका कोई सामूहिक सूचक भी नहीं है। शुरुआत में सभी ने इस मुद्दे पर रुचि दिखाई, लेकिन बाद में सब ठंडे पड़ गए। 2013 में केदारनाथ त्रासदी ने सबको झकझोर दिया, और उत्तराखंड के पर्यावरण को लेकर देश भर में चर्चाएं होने लगीं। तब राज्य केतत्कालीन मुख्यमंत्री ने जीईपी को लेकर बैठक कर इसे सरकारी स्वीकार्यता प्रदान की।शुरुआती दौर में इसके लिए एक तरफसरकार ने कमेटी बनाई, जिसमें प्रमुख शोध संस्थाओं के निदेशकों के साथ डॉ.आरके पचौरी भी थे, जो उस समय टेरी के अध्यक्ष थे। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों खास तौर से अमर उजाला ने इसके लिए लामबंदी की। पर दुर्भाग्य से तत्कालीनमुख्यमंत्री के बदलने के बाद फिर इसमें शिथिलता आ गई। 2018 मेंनैनीताल उच्च न्यायालय ने भी इसे संज्ञान मेंलियाऔर अदालतकेआदेशों कोस्वीकारते हुए सरकार ने भीजीईपी के लिए स्वीकृति प्रदान की। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या जिन समीकरणों से जीडीपी की गणना की जाती है, वही जीईपी की गणना में भी काम आएंगे। देश की विभिन्न शोध संस्थाओं से संपर्क साधा गया। दुर्भाग्यवश सभी के पास एक ही अमेरिकी सूत्र था कि जीईपी की गणना पारिस्थितिकी सेवा की तरह की जाए। लेकिन, पारिस्थितिकी सेवा में हर साल हवा, मिट्टी, जंगल और पानी के जोड़े जाने की सूचना नहीं मिलती, जबकि जीईपी इसका ही सूचक है। थक हार के हैस्को और उसके साथियों ने स्वयं ही इसका बीड़ा उठाया और जीईपी का एक समीकरण बनाया।

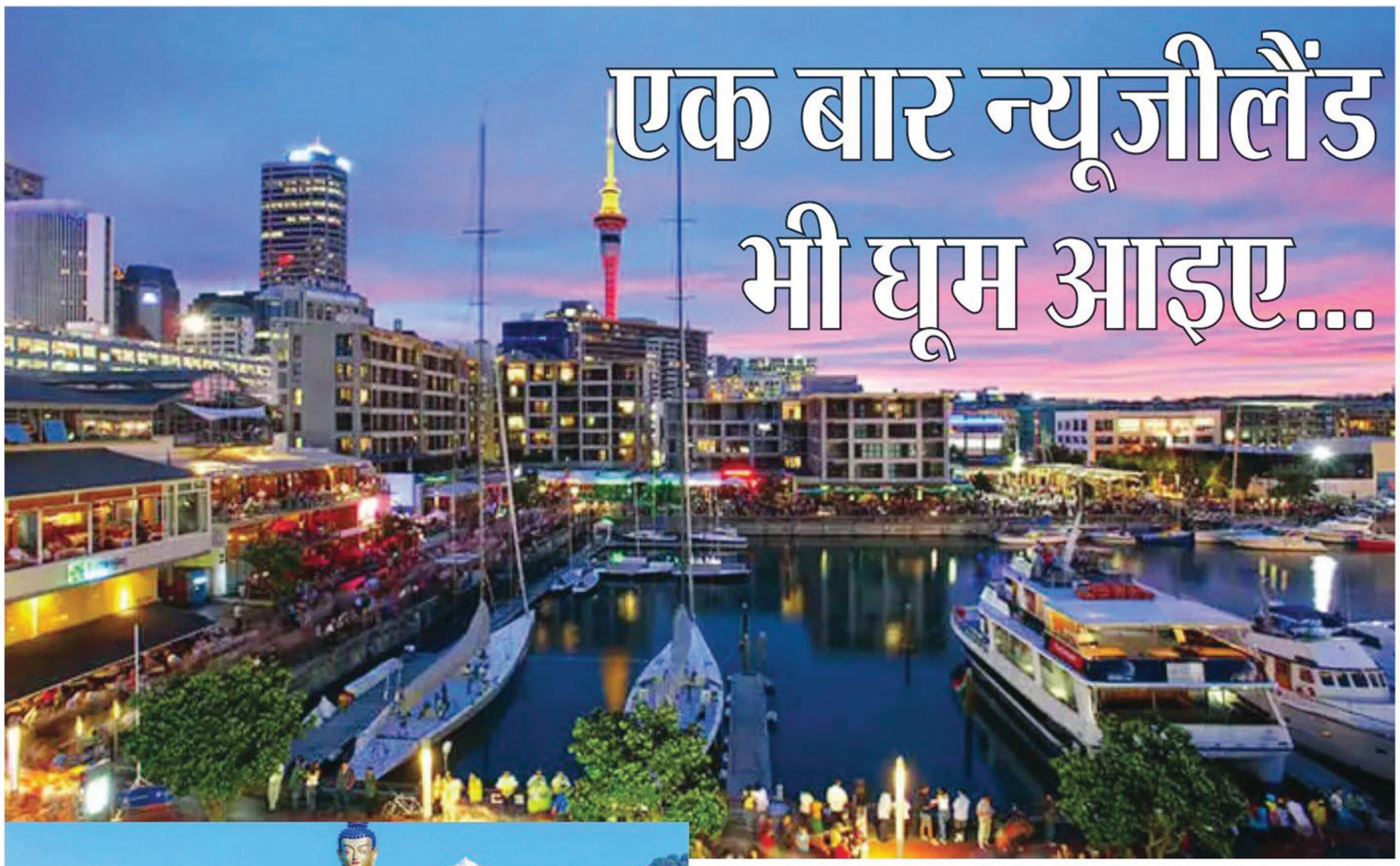

एक बार न्यूजीलैंड भी घूम आइए...

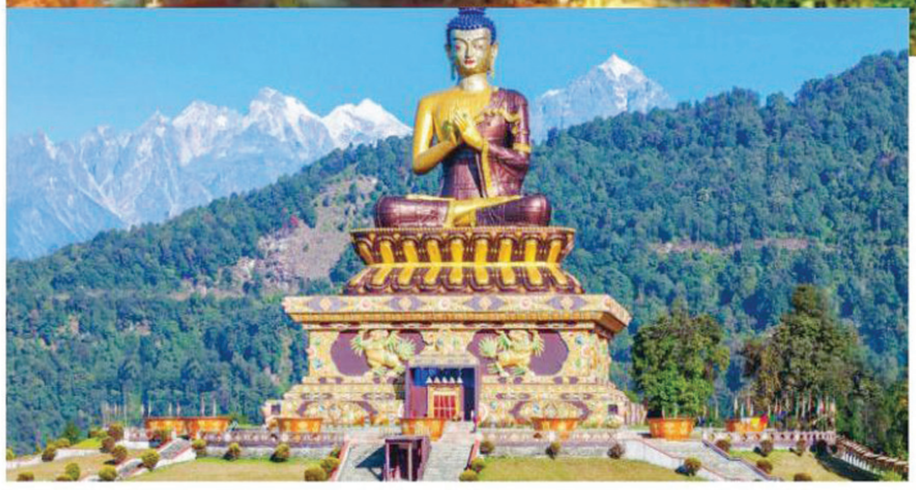

अगर आप सर्दी और क्रिसमस के दौरान विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार न्यूजीलैंड भी घूम आइए...। सर्दी और क्रिसमस की छुट्टियां निकट हैं। छुट्टियों के दौरान अक्सर लोग पर्वतीय, बर्फीले या समुद्री इलाकों में घूमना पसंद करते हैं, तो कुछ परंपरागत लोगों को वाइल्ड लाइफ और कुदरती खूबसूरती से भरे क्षेत्रों में फुर्सत के पलों को बिताना अच्छा लगता है। ऐसे में अगर विदेश में घूमने की प्लानिंग है, तो न्यूजीलैंड परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां बर्फीली चोटियां, झरने, द्वीप, अंगूर के बगीचे, लाल लकड़ियों वाले घने जंगल और दूर तक फैली समुद्र तट सब कुछ हैं।

यहां के नजारे आपको किसी स्वप्न लोक का एहसास कराएंगे। आइए, यहां के कुछ खुशनुमा पर्यटन स्थलों से आपको रूबरू कराते हैं... रोटोरुआ न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप स्थित रोटोरुआ अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से एक रहस्यमयी धरती है और आठवें अजूबे के रूप में दुनियाभर में लोकप्रिय है। इस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी हासिल है। यहां जमीन के अंदर से हर समय निकलते गर्म पानी के बुलबुलों को काफी उत्सुकता से लोग देखते हैं।

जमीन के गर्म पानी में वार्मबाथ लेने के लिए सैलानियों में यह क्षेत्र खूब लोकप्रिय है। इस जगह के कई और भी आकर्षण हैं। अगर आप यहां आएं, तो फ्लोटप्लेन और जेट बोटिंग का आनंद जरूर उठाएं। कंक्रीट के बने रनवे की बजाय पानी के ऊपर से ही ये प्लेन उड़ान भरते हैं। फिर सैलानियों को रोटोरुआ की हवाई सैर कराते हैं। ऊपर से शहर का प्राकृतिक नजारा देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एडवेंचर के शौकीनों को भी यहां करने के लिए बहुत कुछ है, इनमें माउंटेन बाइकिंग, स्काई डाइविंग सैलानियों को खूब पसंद आती है।

अनुपम हैं प्राकृतिक नजारें-- नेपियर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर को माओरी भाषा में अहुरिरी कहा जाता है। यहां का हॉक्स बे इलाका पहाड़, समुद्रतट, बंदरगाह और हवाई अड्डे के कारण पर्यटन का मुख्य केंद्र है। लोग यहां दशकों पुरानी आर्ट डेको वास्तुकला को भी निहारने आते हैं। यहां का मियामी बीच काफी चर्चित है। खाने के शौकीन लोग अक्सर यहां खिंचे चले आते हैं, क्योंकि वाइन और फूड के लिए नेपियर काफी मशहूर है।

ऑकलैंड समुद्र तटों का आनंद उठाने के लिए ऑकलैंड बेहतरीन जगह है। यहां का सबसे बड़ा आकर्षण पानी के भीतर का सैर है। सैलानी इस यादगार लम्हे का लुत्फ उठाने से नहीं चूकते। चाहें तो यहां के नाइंटी माइल बीच पर गोताखोरी के साथ-साथ डॉलफिन मछलियों के साथ तैराकी का मजा भी ले सकते हैं। समुद्रतटों पर बने रिसॉर्ट में ठहरने का भी अपना एहसास है। यहां की रंगारंग पार्टियां, कसीनो, हॉट एयर बैलूनिंग, घुड़सवारी, बच्चों का एडवेंचर पार्क, क्लॉक म्यूजियम, काऊ वर्ल्ड पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। ऑकलैंड खरीदारी के लिए भी अच्छी जगह है। यहां कई फेमस रेस्टोरेंट और दुकानें हैं।

प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बेस्ट हैं राजस्थान की ये जगहें, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप

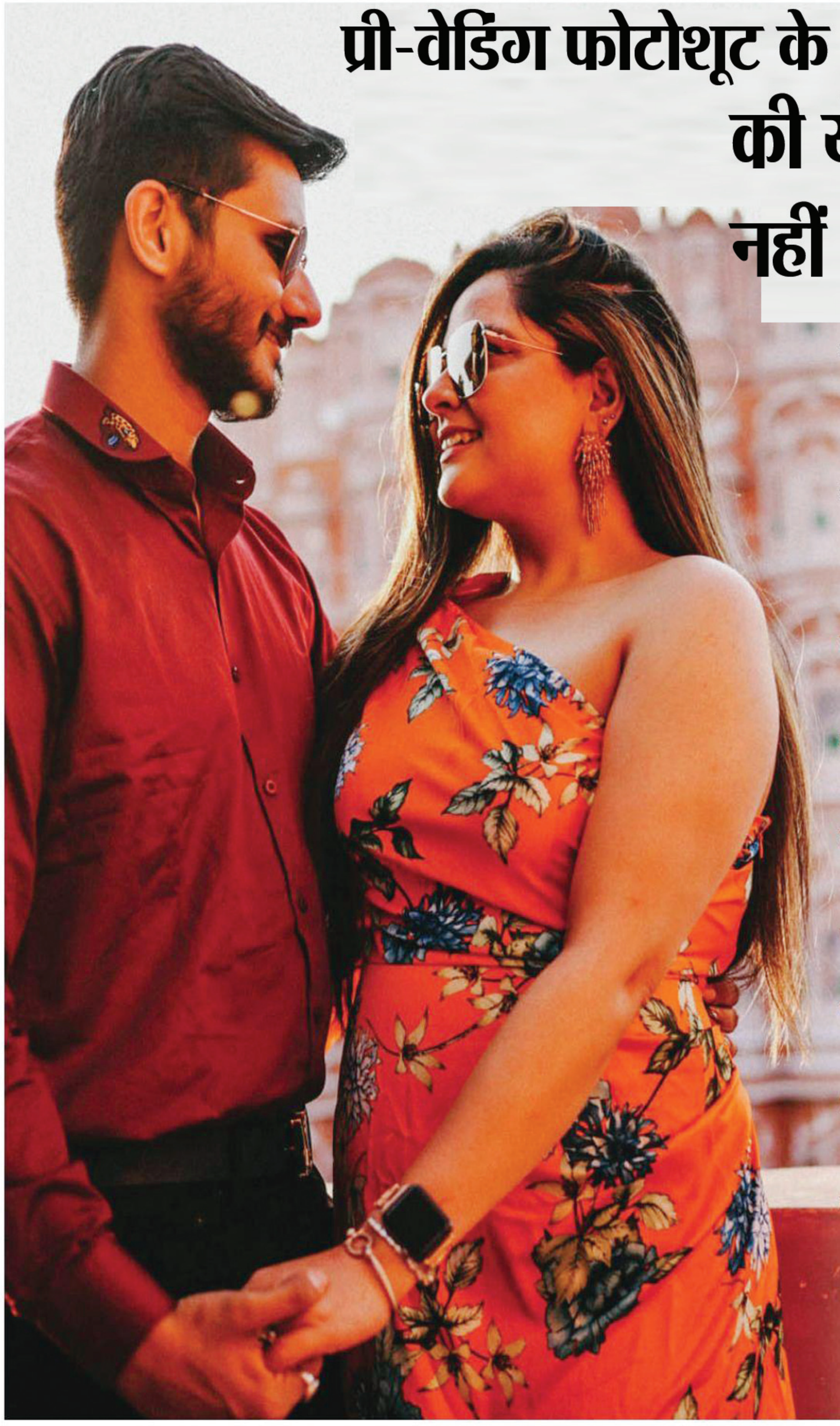

हम सभी यादों को कैद करने के लिए तस्वीरें लेते हैं। वहीं शादी के पलों को खासकर अपनी यादों में संजोना चाहते हैं। जैसे शादी से पहले प्री-वेडिंग फोटोशूट, पोस्ट वेडिंग शूट, मैटरनिटी शूट करवाते हैं। जिससे कि इन तस्वीरों को हम जब भी देखें, तो इन खूबसूरत पलों को यादकर मुस्कुरा सकें। इस सब के बीच आजकल के कपल्स प्री वेडिंग फोटोशूट करवाना पसंद करते हैं।

ऐसे में अगर आपकी भी शादी होने वाली है और आप भी प्री वेडिंग शूट के लिए खूबसूरत जगहों की तलाश कर रहे हैं। तो बता दें कि यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको राजस्थान की कुछ बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। राजस्थान में आपको कई ऐसी लोकेशन मिलेंगी। जो आपको रॉयल फील देने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं उन जगहों के बारें में जहां पर आप प्री वेडिंग शूट करवा सकते हैं।

मंडावा- अपनी खूबसूरत नक्काशी और कृतियों वाली हवेलियों के लिए जाना जाने वाला मंडावा रिच कल्चरल हेरिटेज डेस्टिनेशन है। ऐसे में आप यहां पर फोटोशूट करवा सकते हैं। शादी के सीजन में कई कपल्स यहां पर फोटोशूट करवाते हैं।

बूंदी - राजस्थान का बूंदी शहर अपने भव्य महलों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। यह हवेलियां और महल आपकी प्री-वेडिंग शूट को रॉयल लुक देने का काम करेगा। आप यहां पर तारागढ़ किला, रानी जी की बावड़ी आदि में अपना शूट करवा सकते हैं।

शेखावाटी एरिया- आपको बता दें कि शेखावाटी एक ओपन एयर आर्ट गैलरी है। यहां की हवेलियों में खूबसूरत पेंटिंग हो रखी है। प्री-वेडिंग शूट के लिए यह लोकेशन सबसे बेस्ट है। शेकावाटी एरिया का खूबसूरत लोकेशन आपके प्री-वेडिंग शूट में चार चांद लगाने का काम करेगा।

रणकपुर- रणकपुर 15वीं शताब्दी के जैन मंदिरों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। रणकपुर में कई ऐसी जगहे हैं, जहां पर आप प्री-वेडिंग शूट करवा सकते हैं।

भरतपुर- राजस्थान का भरतपुर अपने नेचर और वाइल्डलाइफ के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर आप भी प्री-वेडिंग शूट में वाइल्डलाइफ और नेचर का टच देना चाहते हैं, तो यह जगह परफेक्ट है। इसके अलावा भरतपुर में आप लोहागढ़ किले में भी शूट करवा सकते हैं।

खिमसर- दरअसल, यह गांवनुमा एक रिज़ॉर्ट है। यह जगह खिमसर किले और थार डेजर्ट के लिए जानी जाती है। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए काफी फेमस है। ऐसे में यहां पर प्री वेडिंग शूट करवाना एक यूनिक आइडिया हो सकता है।

कुंभलगढ़- कुम्भलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमन्द ज़िले में स्थित एक दुर्ग है। हांलाकि इस जगह को लोगों द्वारा काफी कम एक्सप्लोर किया गया है। ऐसे में यहां पर आपको प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी हरियाली देखने को मिलेगी। वहीं प्री-वेडिंग शूट के लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन है।

भैंसरोड़गढ़- कई कपल्स प्री वेडिंग शूट के लिए थोड़ा यूनिक जगह की तलाश कर रहे हैं, तो भैंसरोड़गढ़ आपको निराश नहीं करेगा। भैंसरोड़गढ़ में नेचर और चंबल नदी का किनारा आपके शूट को खूबसूरत बनाने का काम करेगा।

सफर के दौरान इन चीजों का सेवन हो सकता है हानिकारक

लंबी छुट्टियों के दौरान हर कोई पूरे परिवार के साथ कहीं न कहीं घूमने जाने का प्लान बनाता है। गर्मियों की छुट्टी हो या वेकेशन हिल स्टेशन जाने का अपना ही मजा होता है। कई लोग सफर के दौरान गाने सुनते हैं तो कोई किताब पढते हैं तो कोई आराम करते हैं। सफर के समय भूख लगना एक बहुत ही ज़ाहिर सी बात हैं। हम घर से काफी सारी चीजें लेकर जाते हैं सफर के लिए लेकिन सफर में हम और चीजें भी खरीद लेते हैं। जिससे कई लोगों को सफर के दौरान उल्टी, जी मचलने की, सर घूमने की शिकायत रहती है और ऐसा होने पर सफर का मजा फीका पड़ जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सफर में कि चिजों का सेवन हानिकार साबित हो सकता है।

तला हुआ खाना - ध्यान रहे कि सफर में कभी भी आप तले हुए खाने का सेवन ना करें ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता हैं। ट्रेन से यात्रा के दौरान कई बार स्टेशन पर समोसे, कटलेट जैसी चीजें मिलती हैं। इन्हें देखकर मन ललचाने लगता है और हम भूख न लगने पर भी इनका सेवन कर लेते हैं। बाहर खुले में बिकने वाली इन चीजों को यात्रा के दौरान खाने की गलती न करें।

नॉन वेज - अगर आप सफर के दौरान नॉन वेज खाते हैं तो वह आपके पेट के लिए सहीं नहीं हैं क्योंकि नॉन वेज काफी हेवी होता हैं और उसे पचने मे काफी समय लगता हैं और सफर में हम सिर्फ बैठे रहते हैं और हम ज्यादा हिल डुल नहीं सकते हैं जिससे नॉन वेज पच नहीं पाता हैं। इसलिए ध्यान रहें कि आप सफर के समय में हल्की चीजों का सेवन करें।

दूध अंडा - दूध और अंडा भी काफी भारी होते हैं हमारे पेट के लिए और इन्हें पचने में काफी समय लगता हैं तो अगली बार जब भी आप सफर करें तो ध्यान रहें कि आप दूध और अंडे का सेवन ना करें ताकी आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हों और आपका सफर अच्छे से बीते।

केले के चिप्स - सफर के दौरान आप सूखे केले के चीप्स खा सकते हैं। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा एक मुट्ठी बादाम, भूने हुए चने, पिस्ता, सूखे कॉर्नफ्लैक्स और मूंगफली को हल्का सा सरसों के तेल या ऑलिव ऑयल में फ्राई करके पैक करके रख लें। इनके अलावा आप सेब और केले का सेवन भी कर सकते हैं।

नवविवाहित जोड़ों के लिए ये हैं 5 सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशंस

अपने पार्टनर के साथ कुछ पल अकेले गुजारना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। खासकर न्यूली वेड्स के लिए तो ऐसा करना बेहद यादगार हो सकता है। यहां है कुछ खास रोमांटिक डेस्टिनेशंस की लिस्ट, जहां आप अपने स्पाउस के साथ जाने की तैयारी कर सकते हैं।

पॉन्डिचेरी- 1499 में वास्को डी गामा ने इसे डिस्कवर किया था। पॉन्डिचेरी या पुडुचेरी दुनिया की सबसे ज्यादा रोमांटिक डेस्टिनेशंस में से एक है। यहां के फ्रेंच कोलोनियल बिल्डिंग्स और खूबसूरत चर्च देखने लायक हैं। होटल कोरामंडल हेरिटेज में आप एक आरामदायक स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोमेनेड और ले रॉयल पार्क भी अच्छे होटल साबित होंगे। स्वाद का आनंद उठाना चाहते हैं तो कैफे जटासी, सत्संगा, बेकर स्ट्रीट बेस्ट हैं। पॉन्डिचेरी जाएं तो प्रोमेनेड बीच, पैरेडाइज बीच, ऑरोविल बीच, सेरेनिटी बीच बिलकुल भी मिस नहीं करें।

वेनिस- इटली का वेनिस भी दुनिया की बेहद रोमांटिक जगह में शामिल है। यहां के खूबसूरत कैनाल इस जगह के चार्म और मूड में चार चांद लगा देते हैं। ग्रिटी पैलेस, कार्निवल पैलेस और मोरेस्को जैसे होटल, वेनिस में रहने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। कैनाल में एक शानदार बोट-राइड न्यूली-वेड्स के लिए यादगार साबित होगी। ये गोंडोला राइड्स के नाम से मशहूर हैं। कैनाल के अलावा पियाजा सैन मार्को भी जरूर देखें। यहां के ला जुका, रिवेरिआ और अल मेरका जैसे रेस्ट्रॉन्ट्स भी बेहद पसंद आएंगे। कुलमिलाकर प्यार को सेलेब्रेट करने के लिए वेनिस से अच्छी जगह नहीं होगी।

बोरा बोरा- बोरा बोरा को परफेक्ट लवर्स पैरेडाइज भी कहा जा सकता है। ये न्यूलीवेड्स के लिए आदर्श हनीमून डेस्टिनेशन है। यहां का माहौल किसी सपने जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो आप दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। एक कोजी स्टे के लिए आप होटल ले मेरीडियन, होटल मैटेयी और ब्लू हेवन आइलैंड ट्राय करें। रेस्ट्रॉन्ट्स में ला विला महाना, द लकी हाउज और ते पहु में शानदार मील्स लिए जा सकते हैं। यहां का सनसेट आप अपने पार्टनर के साथ खूब एन्जॉय करेंगे।

पैरिस- खुद को एक परफेक्ट रोमांटिक फैंटेसी में देखना चाहते हैं तो पैरिस से अच्छा कुछ नहीं। यहां के होटल रेसिडेंस फो, एक्रोपोल और शांग्रीला में रोमांटिक और बेहद आरामदायक स्टे किया जा सकता है। इस सिटी में अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर पैदल घूमने का अलग ही मजा है। नोट्रे डेम या आइकॉनिक एफिल टॉवर में पिक्चर्स क्लिक करवाएं। पैरिस का माहौल आपकी मैरिड लाइफ में काफी रस घोल सकता है।

कॉट्सवोल्ड्स- इंग्लैंड का कॉट्सवोल्ड्स हनीमून के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां आपको बहुत प्रिवेसी मिलेगी और साथ ही फिशिंग, स्विमिंग और बोटिंग एन्जॉय करने का वक्त भी मिलेगा। कॉट्सवोल्ड्स में ओल्ड स्टॉक इन, मेटाइम इन और बार्न्सले हाऊस में स्टे करें और यहां के अद्भुत व्यू का आनंद उठाएं। वारविक कासल, एवॉन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे लैंडमार्क्स बिलकुल मिस नहीं करें। सबसे अच्छा खाना खाने के लिए ल्युमिएर, ग्रेप एस्केप और डिनर एट सिक्स जाएं। इस जगह की हरियाली आपके अंदर के नेचर लवर को बाहर निकाल कर ले आएगी। यहां के पार्क में एक रोमांटिक पिकनिक करें। ये आपकी यादों में हमेशा बनी रहेगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राज्यसभा में धनखड़ ने की संघ की तारीफ तो भड़के सिब्बल

नई दिल्ली। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कसीदे पढ़े जाने पर सियासी विवाद गहरा गया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उच्च सदन के सभापति का बयान परंपरा के बिल्कुल उलट है। इस तरह की राय एक सदस्य रख सकता है, मगर सभापति नहीं। दरअसल, जगदीप धनखड़ ने बुधवार को आरएसएस पर टिप्पणी करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने आरएसएस की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्र की सेवा में लगा संगठन है और संगठन से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। देश के काम में लगे संगठन की आलोचना करना संविधान के खिलाफ है और उसे देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का अधिकार है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें टोकने की कोशिश भी की थी। इस हंगामे के बाद विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था।

राहुल गांधी के वायनाड दौरे पर भाजपा का तंज

नई दिल्ली। केरल के वायनाड में मंगलवार को मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में गुरुवार को पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी के दौरे पर भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सांसद रहने के दौरान वह (राहुल) पांच साल गैरमौजूद रहे। भाजपा नेता सीआर केसवन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, स्पष्ट तथ्य यह है कि राहुल गांधी पिछले पांच वर्षों से वायनाड के संसद सदस्य के रूप में वहां अनुपस्थित रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहादूर भारतीय सेना केरल के वायनाड में हमारे भाइयों और बहनों को निस्वार्थ भाव से बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में इसी सेना का जातिगत आधार पर राजनीतिकरण करने की कोशिश की थी। हम इसे नहीं भूल सकते हैं।

केजरीवाल के पीए बिभव को सुप्रीम कोर्ट की लताड़

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने (बिभव कुमार) इस तरह आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार के वकील से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है? क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हत्यारों और लुटेरों को जमानत मिल सकती है, लेकिन मालीवाल के मामले में बिभव कुमार पर जो आरोप हैं, हम उन्हें खुले में भी नहीं पढ़ना चाहते। जब मालीवाल ने बिभव को शारीरिक समस्या की वजह से मारपीट न करने की अपील की थी, तब भी ये व्यक्ति नहीं रुका! वह क्या सोच रहा था, सत्ता इसके सिर चढ़ गई थी?

25 से घटाकर 21 साल करें चुनाव लड़ने की उम्र : राघव चड्ढा

नईदिल्ली। राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाने की मांग की। अपने बयान में राघव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और हमारी 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। युवा नेता ने यह भी कहा कि आजादी के बाद जब पहली लोकसभा चुनी गई तो 26% सदस्य 40 साल से कम उम्र के थे और जब 2 महीने पहले हमारी 17वीं लोकसभा चुनी गई तो केवल 12% सदस्य 40 साल से कम उम्र के थे। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि हम बूढ़े राजनेताओं वाला एक युवा देश हैं, हमें युवा राजनेताओं वाला एक युवा देश बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा भारत सरकार को एक सुझाव है कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए।

संसद भवन के बाहर राजद ने किया प्रदर्शन

नईदिल्ली। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। गुरुवार को राजद ने बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। आरक्षण के बढ़ाये गए दायरे को संविधान की नौंवी अनुसूचि में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी ने यह प्रदर्शन किया है। इस दौरान राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग की गयी थी। इस मांग की जरूरत उन्होंने आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को सुरक्षा देने के लिए बताया। गुरुवार को संसद परिसर में राजद ने आरक्षण से जुड़ी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजद सांसदों ने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। उन्होंने जो पोस्टर हाथ में लिए थे उसमें लिखा था कि 'बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों और आदिवासियों के लिए बढ़ायी गयी 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो।'

रेल हादसों पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा तो भड़के रेल मंत्री

■ **कहा- हम उनमें से नहीं जो रील्स बनाते हैं**

नई दिल्ली। रेल हादसों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दी है। 30 जुलाई को झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में मुंबई-हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इसपर अब लोकसभा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हम उन लोगों में से नहीं जो रील्स बनाते हैं।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देता हूं कि रेलवे की सबसे बड़ी जो समस्या थी कि निवेश की कमी है वो उन्होंने पीएम मोदी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड आवंटन करके लगातार कई वर्षों तक बजट

आवंटन बढ़ा कर जो सबसे बड़ी समस्या थी उसे दूर किया। मैं रेलवे के उन 12 लाख कर्मचारियों, उस रेल परिवार को भी धन्यवाद देता हूं जो हर दिन 20 हजार से ज्यादा ट्रेनें चलाते हैं और देश की सेवा करते हैं।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो यहां चिल्ला रहे हैं, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 वर्षों में भी वे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) को क्यों नहीं ला पाए? आज वे यहां सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं, तह वह दुर्घटना के आंकड़े देती थी, जो 0.24 से घटकर 0.19 हो गए। ये लोग तब सदन में ताली बजा रहे थे। आज जब यह आंकड़ा 0.19 से घटकर 0.03 हो गया, तो ये दोष लगा रहे हैं। क्या यह देश ऐसे ही चलेगा? कांग्रेस सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी की मदद से झूठी बातें उछालती है। क्या वे उन दो करोड़ लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमेशा रेल से यात्रा करते हैं? विपक्ष पर तंज कसते हुए वैष्णव ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं, जो रील्स बनाते हैं। हम मेहनत करते हैं, न की आप लोगों की तरह जो दिखावा के लिए रील्स बनाते हैं।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लोको पायलटों के औसत कामकाज और आराम करने का समय 2005 में बनाए गए नियम के तहत तय किया जाता है। 2016 में इन नियम में कई सुधार किए गए और लोको पायलटों को अधिक सुविधाएं दी गईं। रेल मंत्री ने आगे बताया कि जनरल कोचों की मांग बढ़ गई है। यह सुविधाएं उन लोगों के समय शून्य थी, जो आज रील्स बनाकर सहानुभूति दिखाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए लगभग 2,500 जनरल कोचों का उत्पादन जल्द पूरा हो जाएगा। प्रत्येक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम चार जनरल कोच होंगे।

सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर हमला

खटाखट करने वालों को 2027 में सफाचट कर देंगे: आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा-कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगो ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया है लेकिन काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफाचट कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार को 10 साल हो गए लेकिन आज तक संविधान नहीं बदला गया। सपा-कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र को कुचला था। आज सपा के लोग उन्हीं के साथ मिलकर संविधान बचाने की बात कर रही है। इसका जवाब 2027 में मिलेगा। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सदन में पेश किए गए 12 हजार 209 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा की और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कहा कि ये बजट यूपी के सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस वर्ष पेश किए गए मूल बजट की 40 प्रतिशत राशि को अलग-अलग विभागों के लिए आवंटित कर दिया गया है। वहीं, 20 प्रतिशत खर्च हो चुका है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी है और प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी सहायक हुआ है। 2017 के पहले प्रदेश के सामने पहचान का संकट था पर अब प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है यही कारण है कि प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 16 से 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इससे प्रदेश में सात लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक नए भारत का दर्शन कराया है। बीते 10 वर्षों में देश की प्रतिव्यक्ति आय और जीडीपी बढ़ी है। 2014 के पहले भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था जो कि अब विश्व में पांचवे स्थान पर आ गया है। आगे आने वाले तीन वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश

■ **विपक्ष ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाए**

नई दिल्ली। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज की प्रणाली को मजबूत करने के लिए गुरुवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने इस कदम की संवैधानिकता पर सवाल उठाए।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान की सूची-1 और सूची-2 में केंद्र और राज्य के विषय से संबंधित कोई भी प्रविष्टि आपदा प्रबंधन से जुड़ी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को समवर्ती सूची में

संशोधन करना चाहिए, ताकि आपदा प्रबंधन के मुद्दे को कवर करने के लिए उचित प्रविष्टि हो सके। उन्होंने कहा कि कानून की विधायी शक्ति को उचित तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। तिवारी ने यह भी कहा कि विधेयक में केंद्र की नियम बनाने की शक्ति राज्यों की शक्तियों पर अतिक्रमण करती है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सौगर रे ने कहा कि अधिकारियों की बहुलता भ्रम पैदा करेगी। बांद में इस विधेयक को ध्वनिमत से पेश किया गया। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्यों के अधिकारों में कोई दखलंदाजी नहीं है और आपदा प्रबंधन राज्यों की पहली जिम्मेदारी है।

विधेयक के उद्देश्यों के मुताबिक, 2005 के अधिनियम का मुख्य मकसद आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र बनाना है। 2005 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारी और निगरानी के लिए जरूरी संस्थागत तंत्र बनाना है। इसके उद्देश्य को हासिल करन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कुछ प्राधिकरण और समितियां स्थापित की गईं हैं।

सरकार ने कहा कि विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने और पिछली आपदाओं से सीख लेने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 20225 की समीक्षा की गई है। अब अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना जरूरी हो गया है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों व समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाने का प्रयास करेगा।

जाति विवाद के बीच अनुराग ठाकुर ने फिर साधा राहुल गांधी पर निशाना

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को जाति जनगणना पर अपने भाषण पर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी टिप्पणियों के कारण कुछ लोगों के अधिकार की भावना आहत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिए गए बयान से कुछ लोगों की अधिकार भावना को ठेस पहुंची, नतीजा यह हुआ कि पूरा इकोसिस्टम चिल्लाने लगा। उन्हें लगता है कि केवल वे ही प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़े वर्ग के लोगों को बुद्धू कहते थे...उनके पूर्वज दलितों और आदिवासियों को समानता न देने का बहाना बनाते थे।

इससे पहले बुधवार को, विपक्षी कांग्रेस ने लोकसभा में राहुल गांधी की जाति के बारे में ठाकुर की टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस के जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को विशेषाधिकार शिकायत सौंपी। चन्नी के नोटिस में लिखा कि पीएम द्वारा लोकसभा की कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणियों को ट्वीट करना स्पष्ट रूप से पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के समान है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें और मुझे इसे पेश करने की अनुमति दें, अनुरोध है कि विशेषाधिकार कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। प्रधान मंत्री के खिलाफ पहल की गई।

खेल
प्रमुख समाचार

स्वप्निल कुसाले ने भारत को दिलाया तीसरा मेडल

पेरिस। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के तीसरे मेडल का इंतजार खत्म हो चुका है। स्वप्निल कुसाले ने गुरुवार को शूटिंग की मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये पहली बार है, जब किसी भारतीय निशानेबाज ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है।

भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करके इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि पहली बार है जब किसी भारतीय निशानेबाज ने इस श्रेणी में पदक जीता है। कुसाले ने शैटॉरौक्स के नेशनल शूटिंग सेंटर में आयोजित फाइनल में 451.4 अंक बनाए।

शुरुआत में, कुसाले नीलिंग स्टेज के बाद 153.3 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर थे। प्रोन स्टेज के अंत तक उन्होंने 310.1 के कुल स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर जगह बनाई, और तीसरे स्थान पर मौजूद यूक्रेन के सेरही कुलिश से सिर्फ़ 0.6 अंक पीछे रहे। अपने पहले पांच स्टैंडिंग शॉट्स में, उन्होंने 51.1 स्कोर किया, चौथे स्थान पर पहुंचे और सिर्फ़ 0.4 अंकों से तीसरे स्थान पर पहुंचे।

अंतिम दौर में तीन चरण होते हैं-घुटने टेकना, लेटना और खड़े होना, प्रत्येक चरण में 15 शॉट शामिल होते हैं। इन चरणों के बाद, एक एलिमिनेशन राउंड होता है। कुसाले ने क्वालीफाइंग राउंड में तीन पोजीशन से 38 इनर 10 (इन्नर) सहित कुल 590 स्कोर के साथ सातवां स्थान हासिल किया था।

यह कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत का तीसरा पदक है। पहला पदक तब मिला जब मनु भाकर ने सोमवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भाकर ने इसी स्पर्धा के मिश्रित टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ एक और कांस्य पदक जीतकर फिर से इतिहास रच दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

निफ्टी ने पहली बार छुआ 25,000 का लेवल

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार पांचवें दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी के बाद बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए। निफ्टी ने आज पहली बार 25,000 का लेवल पार किया। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 126.21 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 81,867.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 81,700.21 और 82,129.49 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 59.75 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर पहली बार 25,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल को पार करते हुए 25,010.90 के ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,956.40 और 25,078.30 के रेंज में कारोबार हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 15 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले इंडिया और अदाणी पोर्ट्स सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स रहे।

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार जुलाई में पड़ी धीमी

नईदिल्ली। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई माह में मामूली रूप से धीमी रही। नए ठेकों और उत्पादन की धीमी रफ्तार इसकी मुख्य वजह रही। दूसरी ओर लागत दबाव तथा मांग में मजबूती के कारण अक्टूबर 2013 के बाद से बिक्री कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि हुई। गुरुवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित 'एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक' (पीएमआई) जुलाई में घटकर 58.1 हो गया जो जून में 58.3 था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, " भारत के मुख्य विनिर्माण पीएमआई में जुलाई में विस्तार की गति मामूली धीमी रही।

आर्सेलरमित्तल की अप्रैल-जून तिमाही की शुद्ध आय में गिरावट

नईदिल्ली। दुनिया की अग्रणी एकीकृत इस्पात तथा खनन कंपनी आर्सेलरमित्तल की 30 जून 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही में शुद्ध आय 72.9 प्रतिशत घटकर 50.4 करोड़ डॉलर रह गई। कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 186 करोड़ अमेरिकी डॉलर की शुद्ध आय दर्ज की थी। आर्सेलरमित्तल ने एक बयान में कहा, अप्रैल-जून अवधि में कंपनी की बिक्री घटकर 1624.9 करोड़ डॉलर रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 18,60.6 करोड़ डॉलर थी। कंपनी ने कहा कि चीन से निर्यात के कारण इस्पात बाजार अस्थिर स्थिति में आ गया है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदित्य मित्तल ने कहा, " कंपनी का मानना है कि मौजूदा बाजार स्थितियां सतत नहीं हैं। मांग के सापेक्ष चीन के अत्यधिक उत्पादन के कारण घरेलू इस्पात का प्रसार बहुत कम हैज्यूरोप तथा अमेरिका दोनों में इस्पात की कीमतें सीमांत लागत से कम हैं।"

पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना हुआ महंगा

नईदिल्ली। पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक ने सभी अवधि के लिए सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दर में 0.05 प्रतिशत या पांच आधार अंकों की गुरुवार को वृद्धि की, जिससे अधिकतर कंज्यूमर लोन महंगे हो गए। पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि एक साल की अवधि के लिए मानक एमसीएलआर अब 8.90 प्रतिशत होगी, जो पहले 8.85 प्रतिशत थी। इसका इस्तेमाल मोटर वाहन तथा व्यक्तिगत जैसे अधिकतर उपभोक्ता ऋणों के मूल्यांकन में किया जाता है। तीन वर्ष की एमसीएलआर पांच आधार अंक बढ़कर 9.20 प्रतिशत हो गई है। अन्य के अलावा एक माह, तीन माह और छह माह की अवधि के लिए ब्याज दर 8.35-8.55 प्रतिशत के दायरे में होगी। एक दिवसीय अवधि के लिए एमसीएलआर 8.25 प्रतिशत के स्थान पर 8.30 प्रतिशत होगी। नई दरें एक अगस्त 2024 से प्रभावी हो गईं।

ओलम्पिक 2024 में भारत के ऐतिहासिक धमाल की उम्मीदें

ललित गर्ग

एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की तब मिट्ठियां तन गयी, यकीनन ये गर्व के क्षण हैं, जब मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ओलम्पिक में पदक दिलाये। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्द्धा का कांस्य पदक कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड को समेटे हुए है। 28 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग श्रेणी में कांस्य जीतकर मनु पहले ही निशानेबाजी में देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं और अब इस नई कामयाबी के साथ एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने का राष्ट्रीय गौरव एवं ऐतिहासिक कीर्तिमान भी उनके हिस्से आ गया है। दोनों खिलाड़ियों ने जता दिया कि खेलों में ही वह सामर्थ्य है कि वह देश एवं दुनिया के सोये स्वाभिमान को जगा देता है, क्योंकि जब भी कोई अर्जुन धनुष उठाता है, निशाना बांधता है तो करोड़ों के मन में एक संकल्प, एकाग्रता का भाव जाग उठता है और कई अर्जुन पैदा होते हैं। अनूठा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी माप बन जाते हैं और जो माप बन जाते हैं वे मनुष्य के उत्थान और प्रगति की श्रेष्ठ, सकारात्मक एवं राष्ट्र को गौरवान्वित करने की स्थिति है। पेरिस में खेलों के महाकुम्भ ओलम्पिक 2024 के आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा, ऐतिहासिक प्रदर्शन एवं संकल्प भारतीय मनुष्य के मन और माहौल को बदलने का माध्यम बनेगा, ऐसा विश्वास है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से भारत में ऊर्जा का संचार होगा, विश्वास, उम्मीद एवं उमंग जागेगी। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैये को भी ये भारतीय खिलाड़ी नया आयाम देंगे।

शाबाश मनु! तुमने न केवल हरियाणा बल्कि भारतीय लैंगिक भेदभाव की

मानसिकता को चुनौती दी है, मनु की दोहरी सफलता का संदेश साफ है कि 'बेटी पढ़ाओ, खूब खेलाओ।' बेटियां भारत का मान एवं शान बनकर दिखायेंगी। मनु ने दो कांस्य पदक ही नहीं जीते, कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वह ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी ही नहीं बनी, बल्कि भारत की ओर से एक ही ओलंपिक में दो पदक हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी भी बनी। मनु की यह उपलब्धि इस मायने में भी खास है कि टोक्यो ओलंपिक में उसकी पिस्टल में खराबी आने के कारण वह जीत के दरवाजे के बाहर से ही लौट आयी थी। वह लंबे समय तक तकनीकी कारणों से मिली असफलता के तनाव एवं अवसाद से जूझती रही। लेकिन उस असफलता के अवसाद को दरकिनार कर दोहरी सफलता पाना निश्चित रूप से तमाम युवाओं के लिये प्रेरणा की मिसाल बनी है, वास्तव में हमारी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का सशक्त माध्यम बनी है। इस खेलों के महाकुम्भ से निश्चित ही अस्तित्व को पहचानने, दूसरे अस्तित्वों से जुड़ने, विश्वव्यापी पहचान बनाने और अपने अस्तित्व को दुनिया के लिये उपयोगी बनाने की भूमिका बनेगी।

राष्ट्र का एक भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की ठान ले तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। विश्व को बौना बना सकता है। पूरे देश के निवासियों का सिर ऊंचा कर सकता है, भले ही रास्ता कितना ही कांटों भरा हो, अवरोधक हो। देश में प्रतिभाओं और क्षमताओं की कमी नहीं है। चैंपियंस अलग होते हैं, वे भीड़ से अलग सोचते एवं करते हैं और यह सोच एवं कृत जब रंग लाती है तो बनता है इतिहास। हमारे खिलाड़ी कुछ इसी तरह चैंपियन बनकर उभरेंगे, दुनिया को चौंकाएंगे, सबके प्रेरणा बनेंगे, ऐसा विश्वास है। दस मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु और सरबजोत सिंह की कामयाबी कई मायनों में खास है क्योंकि उन्होंने कोरिया के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर यह सफलता हासिल की। कोरियाई टीम में एक वह शूटर भी शामिल थी जिसने रविवार के दस मीटर एयर पिस्टल वर्ग में नये ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। यह जीत इन खिलाड़ियों के मजबूत मानसिक स्तर की ही परिचायक है क्योंकि शूटिंग के खेल में गहरी मानसिक एकाग्रता व ऊंचे आत्मविश्वास की जरूरत होती है।

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 1 से 3 अगस्त तक आयोजित राज्यपालों के त्रिदिवसीय सम्मेलन में राज्यपाल रमेन डेका सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्रीमती रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थीं। समारोह में देश के सभी राज्यों के राज्यपाल उपस्थित थे।

70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि जारी

रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर प्रवास के दौरान आज वहां आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है. महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000-1000 रूपए की 6 वीं किश्त रिमोट का बटन दबाकर हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित राशि जारी की. साथ ही 3061 महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोज़गार के लिए 100 करोड़ रूपए का ऋण का वितरण भी किया. गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर माह एक-एक हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन एप एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी शुभारंभ हुआ.

नवजात बिटिया का सौभाग्य, पहले ही दिन गोद में दुलार मिला मुख्यमंत्री का

जिस समय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महारानी अस्पताल पहुंचे। उसी समय कोंडगांव की मोनिका त्रिपाठी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री बिटिया को आशीर्वाद देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत शुभ घड़ी है। बिटिया के दर्शन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बिटिया को अपने हाथों में लिया और दुलारा।

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है: वित्तमंत्री चौधरी

रायपुर। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं उनके मार्गदर्शन से वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश के बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। केन्द्रीय बजट में देश के विकास की कई योजनाएं शामिल की गई हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके समग्र विकास योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास से ही देश सही मायने में विकसित होगा।

मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित आईआईएम में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा किया गया था। मंत्री श्री चौधरी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक,

सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। यह लैंडलॉक्ड राज्य है, यहां वन और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। इसको मध्य भारत के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और आईआईएम रायपुर के समन्वय से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलने की पूरी संभावनाएं हैं।

इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास, वन हेल्थ मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

कार्यशाला में ''हरित अर्थव्यवस्था मिशन- समय की मांग, पर्यावरणीय लचीलापन के

साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा आपूर्ति और हरित अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक वित्तपोषण के लिए बाजारों की भूमिका'' विषय पर चर्चा की गई। सत्र में मुख्य रूप से वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में हरित पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और नवाचार एवं निजी निवेश के अवसरों की चर्चा की। इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के श्री लैनविन कॉन्सेसाओ, वर्ल्ड बैंक के श्री संदीप कांडा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री ज्ञानेंद्र मणि ने अपने-अपने व्याख्यान दिए।

विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम सत्र में वन हेल्थ मिशन के संबंध में स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, एम्स भटिंडा पंजाब के प्रेजिडेंट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और लीप डिज़ाइन के सीईओ और जॉन हॉपकिंस यूएसए के प्रो. डॉ. आंद्रे नोगीरा ने अपने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ. राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई श्री अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई श्रीमती नीरजा कुदरिमोती और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

गरीबों को जमीन का पट्टा दिया भाजपा सरकार उसे रद्द कर रही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमिहीन गरीबों को सरकारी जमीन और पट्टा देकर भू स्वामी बनाया था। भाजपा की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थाई पट्टों के भू स्वामी अधिकार देने वाले परिपत्र को निरस्त करके गरीबों से भू स्वामी का अधिकार छीनना चाहती है। कांग्रेस सरकार के दौरान दिए पट्टो को निरस्त करके गरीबों को सरकारी जमीन से बेदखल करने जा रही है। भाजपा की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में गरीबों के दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाया गया था अब उनके पट्टो को निरस्त करके उन्हें घर से बेघर करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत जो छूट मिलता था, जिसे गरीबों के जमीन खरीद कर मकान बनाने का सपना पूरा होता था उस छूट का खत्म किया गया और अब वह आवंटन के लिए कांग्रेस सरकार ने जो परिपत्र जारी किया था, उन परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है। यह सरकार की गरीब विरोधी चरित्र है, ये सरकार नहीं चाहती कि गरीबों का खुद का जमीन और खुद का मकान हो।

महतारी वंदन में सभी महिलाओं को राशि नहीं मिल रही - कांग्रेस

रायपुर। महतारी वंदन में सभी पात्र महिलाओं को महतारी वंदन की राशि नहीं मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रू. दिया जायेगा। मुख्यमंत्री और कलेक्टर की पत्नी को भी राशि देने का दावा भाजपा ने किया था। भाजपा के चुनावी वादे के अनुसार 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं को महतारी वंदन की राशि मिलनी चाहिये। लेकिन सरकार बनाने के बाद भाजपा अपने वादे से मुकर गयी है तथा अनेक नियम कानून बना दिया जिसके कारण लगभग चालीस लाख महिलाएं योजना के दायरे से बाहर हो गयी, मात्र 70 लाख महिलाओं को पात्र बताया गया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिन 70 लाख महिलाओं को सरकार ने पात्र बताया है उन सभी के खाते में भी पैसा नहीं जा रहा है। सरकार घोषित 70 लाख में से 25 प्रतिशत महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही है। जुलाई माह में सभी पात्र महिलाओं को राशि नहीं मिली है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर सभी जगह से राशि नही मिलने की शिकायते आ रही है। लोकसभा चुनाव में वोट लेने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को अपात्र बता कर उनका नाम लाभार्थी की सूची से हटा दिया गया था।

ट्रेनिंग से क्षमताओं को बढ़ाएं और चयन के लिए दें अपना बेस्ट : ओ.पी.चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज रायगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन उर्दना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि आप सभी पूरे लगन और मेहनत के साथ इस ट्रेनिंग का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, कमियों को दूर करें। दिसंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके पहले आपके पास काफी समय है तो खुद को अच्छे से तैयार करें और अपना बेस्ट दें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी चयनित हो। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में चयन से युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रूपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए।

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना

रायपुर. छत्तीसगढ़ में सावन लगते ही लगातार

बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है. शुक्रवार को सरगुजा और बिलासपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. बता दें कि अब तक बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1399.8 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 235.0 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है. मौसम विशेषज्ञ गायत्री वाणी ने कहा, आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में लगभग हर जिले येलो अलर्ट्स पर हैं. कल सरगुजा और बिलासपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना है. बीते 15 दोनों के बारिश का रिकॉर्ड प्रदेश में अच्छा है. आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावनाएं देखी जा रही है. नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 581.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है. राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 01 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1399.8 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 235.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है.

तेज रफ्तार कार ने युवती को रौंदा, मौके पर हुई मौत

रायपुर. राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. तेलीबांधा रिंग रोड में तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी सवार 21 साल की युवती को टक्कर मार दी. घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं आरोपी मौके से भागकर खम्हार डीह थाना के पार्किंग में कार खड़ी कर फरार हो गया. सूचना मिलने पर तेलीबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई कर अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, मृत युवती की पहचान वीआईपी रोड स्थित अमलतास सोसाइटी निवासी श्रेष्ठा सत्यपथी के रूप में हुई है. वह अपने पिता जो स्क्क्ष् में तरू के पद पर पदस्थ हैं, उनके लिए दवाई लेने निकली थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ और युवती की मौके पर ही मौत हो गई.

महादेव बने रायपुर आयुक्त, नीलम एक्का बने बिलासपुर संभाग के कमिश्नर

प्रदेश में बड़े पैमाने पर 20 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर

रायपुर। राज्य में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए विष्णु देव साय सरकार ने एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. साय सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों का तबादला कर दिया है. जिन अफसरों का तबादला किया गया है उसमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा की रितु सेन को औद्योगिक विकास निगम और विशेष कर्तव्य अधिकारी से निवेश आयुक्त दिल्ली में तैनात किया गया है.

नीलम नामदेव एक्का बने बिलासपुर कमिश्नर- सरकार की ओर से जारी आदेश में नीलम नामदेव एक्का को बिलासपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है. जनक प्रसाद पाठक को कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा के साथ ही मिशन संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. महादेव कावेरी को जिनके पास संचालक कोष एवं लेखा और अतिरिक्त प्रभार दिया गया था उन्हें रायपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है.

इन अफसरों का हुआ ट्रांसफर

1. ऋतु सैन जो भा.प्र.से. द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह निवेश आयुक्त हैं वो अब छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम (मुख्यालय दिल्ली) का कार्यभार ग्रहण करेंगी.
2. अन्बलगन पी. जो वर्तमान समय में सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग देख रहे हैं उनको सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त मिला है.
3. नीलम नामदेव एक्का को आयुक्त बिलासपुर संभाग का बनाया गया है.
4. जनक प्रसाद पाठक को आयुक्त उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है.
5. जनक प्रसाद पाठक को भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई है.
6. महादेव कावरे को आयुक्त रायपुर बनाया गया है.
7. शारदा वर्मा को सचिव वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, बजट, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग को साथ ही सचिव, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
8. किरण कौशल विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) को चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त बनाया गया है.
9. अनुराग पाण्डेय को बीजापुर कलेक्टर के पद से हटाकर विशेष सचिव के तौर पर मंत्रालय में भेजा गया है.
10. चंदन कुमार को विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है.
11. संजीव कुमार झा भा.प्र.से. को समग्र शिक्षा और वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
12. रजत बंसल भा.प्र.से. आयुक्त को वाणिज्यिक कर (जीएसटी) तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आयुक्त, मनरेगा के साथ आयुक्त, मनरेगा तथा संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
13. पुष्पेन्द्र कुमार मीणा को सचिव, लोक सेवा आयोग एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
14. पुष्पा साहू को स्थानीय निधि संपरीक्षा और अति. प्रभार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है.
15. रितेश कुमार अग्रवाल को संचालक, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ करते हुए, संचालक, पेंशन एवं पंजीयक, फर्म एवं संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
16. प्रभात मलिक कलेक्टर जिला महासमुंद को हटाया गया है.
17. कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह को अब महासमुंद कलेक्टर बनाकर भेजा गया है.
18. प्रभात मलिक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है.
19. जयश्री जैन उप सचिव को मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
20. चंदन संजय त्रिपाठी को कोरिया कलेक्टर बनाया गया है.
21. संबित मिश्रा को कलेक्टर बीजापुर बनाया गया है.
22. वासु जैन को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से जिला नारायणपुर के पद पर भेजा गया है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.